स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–19, अंक–7, आषाढ–श्रावण 2068, जुलाई 2011

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा-4

वहां के वित्त विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि दो अगस्त से पहले कांग्रेस ने ऋण लेने की सीमा नहीं बढ़ाई तो अमरीका में आर्थिक जलजला आ जाएगा।

अनुक्रम

आवरण लेख : अमरीका फिर मंदी में
बलि पर भारत को चढ़ाने की साज़िश
– विक्रम उपाध्याय /4

प्रतिक्रिया
सावधान! जनता जाग चुकी है
– के.एन. गोविन्दाचार्य /7

दृष्टिकोण
आर्थिक संवृद्धि का अमानवीय चेहरा
– डॉ. अश्विनी महाजन /9

अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था पर तिहरा दबाव
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /12

मुद्दा
खाओ अंगारे पीओ धुआं
– अवधेश कुमार /15

चिंतन
अमरीका का असली चेहरा
– डॉ. बनवारी लाल शर्मा /18

अंतर्राष्ट्रीय
अफगानिस्तान में भारत की भूमिका
– डॉ. वेदप्रताप वैदिक /21

सामयिकी
परमाणु करार के दुष्परिणाम
– ब्रह्मा चेलानी /23

पुस्तक समीक्षा
अमिताव घोष की पुस्तक : रिवर ऑफ स्मोक पर कुछ विचार
– कश्मीरी लाल /25

पड़ताल
लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से
विरोध प्रदर्शन करना सहन नहीं
– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल /28

समस्या
पूर्वोत्तर में गहराता खतरा – बलवीर पुंज /32

पर्यावरण : जीवन धारा बचाने का अभियान
– जवाहरलाल कौल /32

पाठकनामा/2, आंदोलन/36

पाठकनामा

नयी आशा और विश्वास की ज्योति स्वदेशी पत्रिका

मुझे स्वदेशी पत्रिका के नियमित अध्ययन, चिंतन, मनन करने से अनूठे आनंद की अनुभूति होती है। देश इस समय विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। हर व्यक्ति अवसाद से गुजर रहा है।ऐसे अंधकारमय समय में सभ्यता और संस्कृति समेत संस्कार और आचार व्यवहार में ह्रास होता जा रहा हैं। कुछ शेष बचने की उम्मीद छूटती जा रही है। ऐसे समय में 'स्वदेशी पत्रिका' के विभिन्न स्तंभों में प्रकाशित विचारोत्तेजक सामग्री जड़ीभूत जनजीवन में नयी आशा और विश्वास की ज्योति जगाती है।

स्वार्थों से प्रदूषित समाज का सुधार तभी होगा जब देश–विदेश के कोन–कोने के लोग 'स्वदेशी पत्रिका' का नियमित अध्ययन, मनन–चिंतन करें और नैतिक मूल्यों को आत्मसात कर व्यवहार में लाएं।

– देवेन्द्रनाथ मोदी, सुभाष नगर, जोधपुर–342002

भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी भारतीय एक हो

भ्रष्टाचार आज कैंसर की तरह पूरे देश में फैलता जा रहा है। मंत्री, पुलिस अधिकारी, नौकरशाह और अन्य सरकारी कर्मचारी दिन–प्रति–दिन भ्रष्टाचार को बढ़ाने में अपना योगदान कर रहे हैं। उन्हें भारत की छवि से कोई लेना देना नहीं है – बस पैसा चाहिए – पैसा। आज आपको मकान बनाना हो, ड्राईविंग लाईसेंस बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, पासपोर्ट बनाना हो, उच्च शैक्षिक संथान में दाखिला लेना हो या कोई टेंडर लेना हो या कोई भी कार्य करना हो। सब जगह रिश्वत ही रिश्वत का चलन है। सरकारी कर्मचारी कालेधन को कमाने में लगा हुआ है और जनता उसमें पिसती चली जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने अनशन किया, वही केन्द्र सरकार ने अन्ना के लोकपाल बिल पर अपना टालू रवैया अपनाया। जब चार जून को भ्रष्टाचार और कालेधन के विरोध में बैठे बाबा रामदेव के शिविर पर हुई पुलिसिया कार्रवाई मानवता को कलंकित करने वाली थी। क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा केवल बाबा रामदेव और अन्ना हजारे का? नहीं यह मुद्दा हम सभी भारतीयों का है। इसलिए हम भारतीय वासियों को एकजुट होकर भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सिपाही के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा ताकि हम अपनी आने वाली नई पीढ़ी को भ्रष्टाचार मुक्त भारत सौंपे न की 'भ्रष्टाचार में डूबा भारत'।

– महेन्द्र कुमार, C-130A, विश्वास पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली–59

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com
अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

अमेरिका में आज भी लोग आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। वे चिंतित हैं कि कार खराब हो गई या नौकरी चली गई तो क्या होगा? वे यकीन से नहीं कह सकते कि बच्चों की कॉलेज की फीस दे पाएंगे या नहीं!

– बराक ओबामा

केंद्र सरकार हिंदुओं के मौलिक अधिकार छीनने के लिए सांप्रदायिक हिंसा निषेध विधेयक लाने जा रही है। इसके पारित होने के बाद देश में हिंदुओं का सकुशल रह पाना मुश्किल हो जाएगा।

– अशोक सिंघल

आजकल की फ़िल्मों में कहानी और गाने उस स्तर के नहीं हैं जैसे 70 के दशक में हुआ करते थे साथ ही समाज को प्रेरणा मिलती थी।

– अमिताभ बच्चन

संपादकीय

राहुल का किसान प्रेमः कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना

किसानों को आजादी के बाद से ही क्या मिला सिर्फ आश्वासन? इनकी पीठ पर चढ़कर सत्ता को छूने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इन्हें सिर्फ मुद्दा माना और उसे भुनाने के लिए हमेशा इनकी कुर्बानी देते रहे। कांग्रेस से ज्यादा किस पार्टी को किसानों की दुदर्शा के लिए जिम्मेदार मानें? पैसठ साल के अपने इस लोकतंत्र में ज्यादातर समय तो कांग्रेस ही केंद्र या राज्यों की सत्ता में रही है। फिर भी कांग्रेस यह कहने की हिम्मत कर रही है कि वह किसानों पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और आंदोलन करेगी। वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। क्यों? संभवतः इसलिए कि एक बार फिर किसानों को बरगलाने का अवसर उत्तर प्रदेश में ही मिलने वाला है। यहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। लगातार कांग्रेस यहां हाशिए पर बनी है। सत्ता में आने की बात तो दूर सत्ता के लिए दावेदारों में भी पिछले दो दशकों से गिनती नहीं हो पा रही है। इस बार मैदान थोड़ा खाली है। बसपा के जुल्मों से, सपा की वादा खिलाफी से भाजपा की निष्क्रियता से और बाकी छोटे मोटे दलों के अप्रासंगिक होने के कारण कांग्रेस को लगता है कि इस बार उनकी दाल गल जाएगी? यह अलग बात है कि उनकी दाल ही काली है। किसान महापंचायत में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चार दिन में उन्होंने किसानों के बारे में जो सीखा वह दिल्ली में बैठ कर नहीं सीख सके। उन्होंने सीखा कि किस तरह किसानों की जमीन की उचित कीमत सरकार नहीं देती, उन्हें धोखा देती है। उन्होंने सीखा कि किस तरह एक निर्दयी सरकार किसानों पर जुल्म करती है। उन्होंने सीखा कि किसानों को सत्ता के साथ जोड़ा जा सकता है। उन्होंने यह भी सीखा कि किस तरह किसानों की पीठ पर बैठकर चुनावी बैतरनी भी पार किया जा सकता है। राहुल गांधी के लिए किसानों का मतलब संभवतः इतना ही है। अगर किसानों की परिभाषा वह इससे विस्तृत कर पाते तो उन्हें पता होता कि देश भर के एक फीसदी से भी कम किसान मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं। 99 फीसदी किसान भूख से लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के कुछ बड़े शहरों की बात छोड़ दे तो किसानों को उनकी भूमि ही गले की फांस बन गई है। खेती छोड़ नहीं सकते और खेती उन्हें कुछ दे नहीं पाती। न तो समय पर उन्हें बीज मिलता है औरा न ,खाद मिलती है। हार मांस को गला कर अनाज पैदा भी किया तो उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। गम या खुशी दोनों अवसरों पर किसान अपनी जगीन बेच कर ही खर्च जुटा पाता है और कभी कर्ज लेकर कुछ करने की हिम्मत करता है तो उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाता है। राहुल गांधी यह सब नहीं जानते नहीं तो किसानों की बात सिर्फ नोएडा और अलीगढ़ में जाकर नहीं करते। उत्तरप्रदेश में ही यदि किसानों की दशा जाननी हो तो उन्हें कुछ दिनों के लिए पूर्वांचल का भी दौरा करना चाहिए। यदि किसानों की दशा से वे इतने ही विचलित है तो उन्हें कुछ दिन के लिए बुंदेलखंड में डेरा डालना चाहिए। ताकि वह सीख सके कि जब सूखे से धरती फटती है तो किसान किस तरह खून के आसूं रोता है। खैर उन्हें उत्तरप्रदेश के किसानों के बारे में ज्यादा मालूम नहीं हो, क्योंकि यहां कांग्रेस काफी दिनों से पराई सी नजर आ रही है। पर महाराष्ट्र तो कांग्रेस के लिए सहोदर है। वहां तो लगभग दस साल से सरकार चल रही है। वहां के किसानों के बारे में आकलन राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया। वे किसानों की भूमि के अधिग्रहण के लिए नये कानून की चिंता में है। पर उन किसानों की चिंता क्यों नही कर पा रहे हैं जो कर्ज के कारण रोज जान दे रहे हैं। विदर्भ का विषय तो उनकी जानकारी में है। कितने परिवारों के आसूं उन्होंने पोछे। चलो मायावती की नीयत खराब है, महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार की नीयत तो सही रही होगी। फिर भी किसान आत्म हत्या कर रहे हैं। आंध्र की हालत भी राहुल जानते होंगे। किसान वहां तबाह हो रहे हैं और न तो राज्य सरकार और न केंद्र सरकार उनकी मदद कर रही है। उनकी खरीफ की फसल बारिश में इस इंतजार में बर्बाद हो गई कि सरकार आएगी उनकी फसलों की उचित कीमत देगी। पर वहां राहुल गांधी नहीं थे। इसलिए किसाानों के साथ अन्याय हो गया। कास राहुल गांधी कुछ और किसानों पर अध्ययन करते। पर क्या करे पूरे देश के किसान परेशान है। कितना अध्ययन करेंगे। पूरी उम्र निकल जाएगी। फिर मकसद चुनाव है अध्ययन नहीं। लोग भी समझते है और किसान भी।

अमरीका फिर मंदी में

बलि पर भारत को चढ़ाने की साज़िश

हाल के दिनों में जो आर्थिक सूचक आकड़ें मिले हैं वे और निराश करने वाले हैं। इस समय अमरीकी विकास दर महज 1.8 फीसदी है। गोल्डमैन साच्स की रिपोर्ट का आकलन है कि इस वर्ष अर्थव्यवस्था में भूचाल आ सकता है। बेरोजगारी की रिपोर्ट और स्याह तस्वीर पेश कर रही है। इस समय अमरीकी में बेरोजगारी वृद्धि दर लगभग 9 फीसदी तक पहुंच चुकी है।

■ विक्रम उपाध्याय

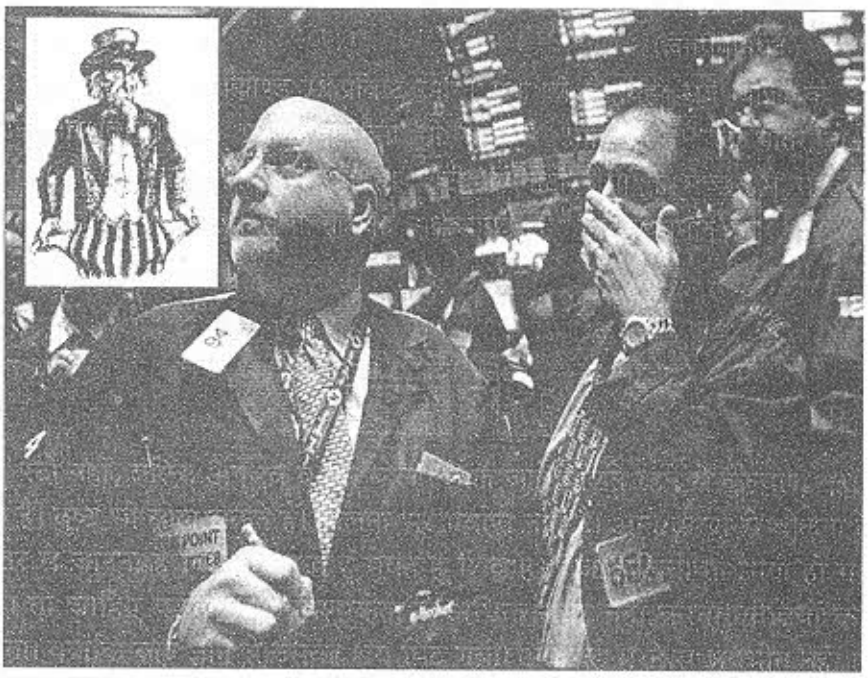

कर्ज की अर्थव्यवस्था अमरीका के लिए फांस बनती जा रही है। वहां के वित्त विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि दो अगस्त से पहले कांग्रेस ने ऋण लेने की सीमा नहीं बढ़ाई तो अमरीका में आर्थिक जलजला आ जाएगा। नौबत यहां तक पहुंच जाएगी कि अमरीकी लोगों को तनख्वाह के लाले पड़ जाएंगे। आशंका यह भी है कि अगस्त के बाद अमरीका अपने नागरिकों दिए जा रहे सामाजिक सुरक्षा भत्ते को रोक सकता है। इस समय अमरीकी सरकार 14.3 खरब डॉलर तक ऋण ले सकती है। यानि इतनी रकम तक के बांड जारी कर सकती है। यदि उससे अधिक ऋण की जरूरत पड़ी तो इसके लिए अमरीकी संसद से मंजूरी लेनी आवश्यक है। 1966 से लेकर अभी तक अमरीकी संसद 40 बार से अधिक ऋण की सीमा बढ़ा चुका है और 2001 से अभी तक दस बार।

वहां के वित्त विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि दो अगस्त से पहले कांग्रेस ने ऋण लेने की सीमा नहीं बढ़ाई तो अमरीका में आर्थिक जलजला आ जाएगा। नौबत यहां तक पहुंच जाएगी कि अमरीकी लोगों को तनख्वाह के लाले पड़ जाएंगे।

स्पष्ट है कि अमरीकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। एक और आर्थिक सुनामी का डर सिर्फ ओबामा प्रशासन को ही नहीं है, बल्कि अब विश्व बैंक भी मिन्नते कर रहा है कि अमरीकी कांग्रेस को ऋण लेने की सीमा बढ़ा देनी चाहिए, नहीं तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

खतरा यह भी है कि ओबामा अपनी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं कर पाएंगे। जिसके कारण अमरीकी

डॉलर पर बुरा असर पड़ेगा। अमरीकी अर्थशास्त्री इस बात के लिए भयभीत हो रहे हैं कि कहीं इस वित्तीय संकट के कारण डॉलर की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा होने की पहचान न खत्म हो जाए उसकी जगह चीन की मुद्रा युआन न ले ले। अमरीका की अर्थव्यवस्था अपने ही कर्ज के बोझ से डूब रही है।

हाल के दिनों में जो आर्थिक सूचक आकड़ें मिले हैं वे और निराश करने वाले हैं। इस समय अमरीकी विकास दर महज 1.8 फीसदी है। गोल्डमैन साच्स की रिपोर्ट का आकलन है कि इस वर्ष अर्थव्यवस्था में भूचाल आ सकता है। बेरोजगारी की रिपोर्ट और स्याह तस्वीर पेश कर रही है। इस समय अमरीकी में बेरोजगारी वृद्धि दर लगभग 9 फीसदी तक पहुंच चुकी है।

अमरीकी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है मांग में कमी आना। लोग अभी भी आवास ऋण और केडिट कार्ड कर्ज के बोझ तले फंसे हुए हैं। हालांकि ओबामा प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि लोगों को आवास ऋण से राहत दिला कर फिर से रियलिटी उद्योग में मांग बढ़ाई जाए। क्योंकि आवास उद्योग के उछाल से अमरीकी बेरोजगारी में कमी आएगी। लेकिन परिणाम उलटा ही मिला। अमीरों ने आवास ऋण पर देय ब्याज में राहत से जो फायदा मिला उसका उन्होंने अपने घरेलू सामानों की खरीद में उपयोग कर लिया। अमरीकी अभी भी मकान खरीदने से कतरा रहे हैं। अमरीकी अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास में कमी इस बात से पता से चलती है कि वहां के दस साल की अवधि वाले बांड पर रिटर्न बमुश्किल तीन फीसदी है।

अमरीकी अर्थव्यवस्था का आधार ही वहां के उपभोक्ता हैं। पूरी अर्थव्यवस्था का 70 फीसदी भार उपभोक्ता बाजार पर है। जहां से मांग काफी कम निकल रही है। लगातार नौकरियां छिनने, केडिट कार्ड के डिफाल्टर होने और आगे और बड़ी समस्या के आकलन से भयभीत अमरीकी नागरिक खर्चे में कटौती कर रहा है।

अमरीकी अर्थव्यवस्था का आधार ही वहां के उपभोक्ता हैं। पूरी अर्थव्यवस्था का 70 फीसदी भार उपभोक्ता बाजार पर है। जहां से मांग काफी कम निकल रही है। लगातार नौकरियां छिनने, केडिट कार्ड

के डिफाल्टर होने और आगे और बड़ी समस्या के आकलन से भयभीत अमरीकी नागरिक खर्चे में कटौती कर रहा है।

अब वहां इस बात पर बहस हो रही है कि क्या सरकार को खर्चे बढ़ाने का उपाय करना चाहिए। कई अमरीकी अर्थशास्त्री मानते हैं कि जब नौकरियां जा रही हैं, निजी क्षेत्र अपने निवेश खींच रहा है और उपभोक्ता शांत बैठा हो तो वैसे में केंद्रीय सरकार को अपने खर्च बढ़ाने चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में हलचल बनी रहे। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ओबामा प्रशासन को लोगों को करों में छूट प्रदान कर ब्याज दर आकर्षक बनाकर फिर से बाजार में उतारना चाहिए।

ओबामा ने ऐसा किया भी है। उनके प्रशासन ने 800 अरब डॉलर का एक ऐसा पैकेज जारी किया है, जिसमें वहां के नागरिकों के लिए करों में राहत से लेकर ऋण से मुक्ति के भी उपाय हैं। लेकिन उसका भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहा है।

अब अमरीका चाहता है कि उसकी आर्थिक समस्या का निराकरण भारत और चीन जैसे देश अपने त्याग से करें। हाल ही में ओबामा ने कहा था कि अमरीकी नागरिकों की नौकरियां भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश खा जा रहे हैं। ओबामा ने यहां तक कह डाला कि अब उनका प्रशासन उन्हीं कंपनियों को करों में छूट या राहत प्रदान करेगी जो अमरीका में रोजगार बढ़ाने के लिए तैयार होंगे।

इसका सीधा मतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम कर रही भारतीय कंपनियों को झटका लगेगा। अब तो आए दिन यह खबर आ रही है कि यहां कॉल सेंटर बंद हो रहे हैं। दरअसल ओबामा प्रशासन को ये आकड़ें सता रहे हैं कि भारतीय आईटी कंपनियों ने अमरीका से प्राप्त कुल आउटसोर्सिंग बिजनेस के 50 से 60 फीसदी भाग पर कब्जा जमा रखा है।

अब अमरीका चाहता है कि उसकी आर्थिक समस्या का निराकरण भारत और चीन जैसे देश अपने त्याग से करें। हाल ही में ओबामा ने कहा था कि अमरीकी नागरिकों की नौकरियां भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश खा जा रहे हैं। ओबामा ने यहां तक कह डाला कि अब उनका प्रशासन उन्हीं कंपनियों को करों में छूट या राहत प्रदान करेगी जो अमरीका में रोजगार बढ़ाने के लिए तैयार होंगे।

ओबामा ने कहा कि उनका प्रशासन उन अमरीकी परिवारों को करों में 95 फीसदी तक छूट देने के लिए तैयार है यदि वे अमरीकियों को यहां रोजगार देते हैं। हालांकि अमरीकी संसद में इस आशय का विधेयक अभी पास नहीं हुआ है लेकिन इसकी तैयारी अभी से होने लगी है। अमरीकी करों में छूट के वायदे का असर दिखने लगा है। हाल ही में कई अमरीकी फर्म जिनका आउटसोर्सिंग बेस भारत में था, ने यहां का काम समेट कर वापस अमरीका चली गई हैं। सिर्फ अमरीकी कंपनियां ही नहीं, लगभग 35 भारतीय कंपनियां भी ओबामा प्रशासन के गुड बुक में चल रही हैं। अमरीका में ये भारतीय कंपनियां लगभग 60 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। ❑

प्रतिक्रिया

भ्रष्टाचार पर सब राजनीतिक दल समान

सावधान! जनता जाग चुकी है

भ्रष्टाचार, कालाधन किसी अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और गोविन्दाचार्य का मुद्दा नहीं है। सबको इस रोग के खिलाफ एकजुट होकर सत्तापक्ष से लड़ना होगा। साथ ही व्यक्तिगत अहम को त्यागना होगा। अनुभव और उदाहरण को देखते हुए कहा जा सकता है कि सत्तापक्ष और विपक्ष में कोई अंतर नहीं रह गया है। नीति और नियति भी सारे राजनीतिक दलों की एक है। हां, यह खुशी की बात यह है कि जनता के द्वारा आंदोलन हो रहा है। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। जनता अब भ्रष्ट सरकारों को सहने के खिलाफ है।

राजनीतिक दलों का आकलन मुख्य रूप से पांच बातों से करने पर स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। ये हैं – प्रेरणा, विचारधारा, कार्यपद्धति, आचरण और व्यवहार। इन बातों को सही रूप से किसी दल में लागू करने के लिए जरूरी है आत्मविलोपन। किसी दल में इसका अभाव हो जाता है तो गड़बड़ियां स्वाभाविक हैं। कोई दल इन बातों को साध लेता है तो वह स्वाभाविक बदलाव का औजार बन जाता है। दुर्भाग्य से आज ज्यादातर दलों में इसका अभाव दिखता है. . .

■ के.एन. गोविन्दाचार्य

सारा देश भ्रष्टाचार, कालेधन और राजनीतिक दलों की अवसरवादिता से परेशान है। पार्टियों के दोहरेपन के कारण किसी मुद्दे पर कोई स्पष्ट नीति नहीं बन पा रही है। देश में राजनीति सामाजिक बदलाव एवं सेवा का माध्यम न होकर पैसे से राजनीति और राजनीति से पैसा बनाने का खेल बन गया है। पार्टियों की सत्तोन्मुख राजनीति के कारण आम कार्यकर्ता हताश–परेशान है।

अधिकतर मुद्दों पर राजनीतिक दलों की राय एक सी बनती जा रही है। शुचिता का अभाव सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। राजनीति में सत्ता, सम्पत्ति और सम्मान का गठजोड़ हो गया है। राजनीतिक दलों का आकलन मुख्य रूप से पांच बातों से करने पर स्थिति और स्पष्ट हो जाती है।

ये हैं – प्रेरणा, विचारधारा, कार्यपद्धति, आचरण और व्यवहार। इन बातों को सही रूप से किसी दल में लागू करने के लिए जरूरी है आत्मविलोपन। किसी दल में इसका अभाव हो जाता है तो गड़बड़ियां स्वाभाविक हैं। कोई दल इन बातों को साध लेता है तो वह स्वाभाविक बदलाव का औजार बन जाता है। दुर्भाग्य से आज ज्यादातर दलों में इसका अभाव दिखता है, जिस दल में इसकी कमी हो जाये वह राष्ट्रीय महत्व के लक्ष्य को पूरा करने में उपयोगी भूमिका नहीं निभा सकता है। ऐसा दल तो सामाजिक व आर्थिक हैसियत बढ़ाने का जरिया भर बनकर रह जाता है। मूल्यों और मुद्दों से भटके राजनीतिक दलों की सरकार भ्रष्टाचार के नये–नये रिकॉर्ड बना रही है।

नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच

की दीवार दिनोंदिन चौड़ी होती जा रही है। राजनीतिक दल राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे को हल करने में नहीं बल्कि उसका राजनीतिक लाभ लेने में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। अभी कहने को लोकपाल के सवाल पर सत्ता व विपक्ष की राय भिन्न है पर विपक्षी दल अपने विचार सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के सवाल पर प्रायः सारी पार्टियों व सरकारों की राय समान है। भारत में समूचे शासक वर्ग ने भ्रष्टाचार, कालेधन और ढेर सारे मुद्दों पर मौन सहमति सी बना ली है। जब तक गरीबपरस्त सरकार नहीं बनती है तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता।

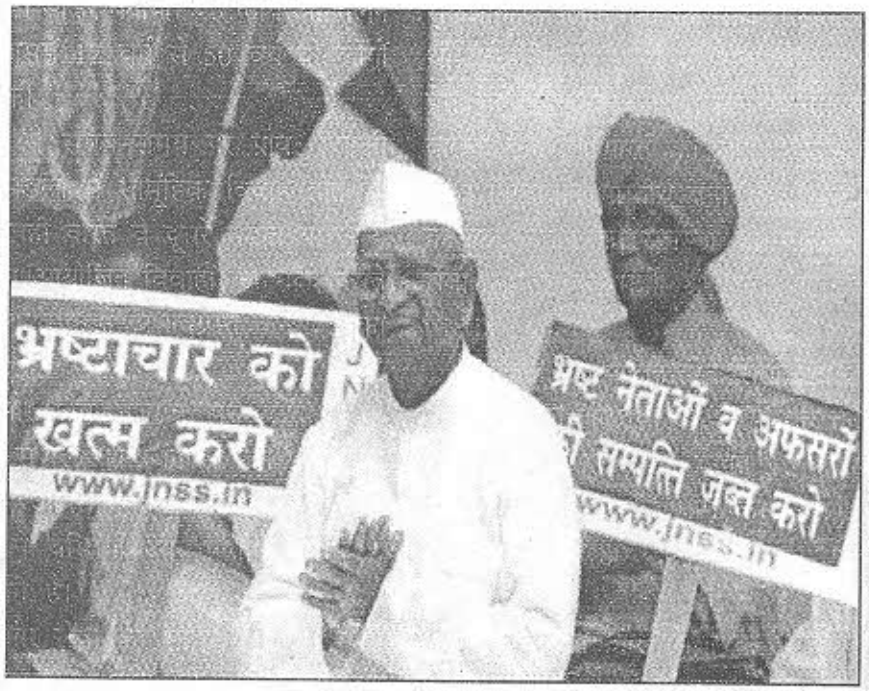

आज जनप्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सांसद, मंत्री, विधायक–सभी जनता के नाम पर पूंजीपतियों और कॉरपोरेट हाउसों के हित में काम कर रहे हैं। ऐसे में जब जनता अपना हक मांग रही है तो उसके नेताओं को जनता का प्रतिनिधि नहीं माना जा रहा है। यह आश्चर्यजनक व खतरनाक संकेत है। मैं सारे राजनीतिक दलों पर दोहरेपन का आरोप लगा रहा हूं। पीएमओ, चीफ जस्टिस को लोकपाल के दायरे में रखा जाए कि नहीं, सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष को भी अपनी राय रखनी चाहिए। पर विपक्ष मौके की तलाश में है। यह राजनीतिक अवसरवाद का चरम है।

भ्रष्टाचार, कालाधन किसी अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और गोविन्दाचार्य का मुद्दा नहीं है। सबको इस रोग के खिलाफ एकजुट होकर सत्तापक्ष से लड़ना होगा। साथ ही व्यक्तिगत अहम को त्यागना होगा। अनुभव और उदाहरण को देखते हुए कहा जा सकता है कि सत्तापक्ष और विपक्ष में कोई अंतर नहीं रह गया है। नीति और नियति भी सारे राजनीतिक दलों की एक है। हां, यह खुशी की बात यह है कि जनता के द्वारा आंदोलन हो रहा है। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। जनता अब भ्रष्ट सरकारों को सहने के खिलाफ है।

ऐसे में अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन बढ़ेगा। साथ ही सरकारी दमन बढ़ने की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। लोकपाल बिल पर शुरू से ही सरकार का रवैया टालू है। जनाक्रोश को कम करने के लिए यूपीए सरकार ने लोकपाल बिल बनाने की बात मंजूर की थी। उसके बाद ही वह रामदेव के मुद्दे पर दमन पर उतर आई। इससे उसकी गम्भीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। पहले दिन से ही सरकार गलतबयानी व धोखा देने पर उतारू है। शातिर लोगों से अन्ना सदाशयता की उम्मीद क्यों पाले हैं? लोकपाल, भ्रष्टाचार और कालेधन पर सबको एकजुट होकर सरकार की मंशा को बदलना होगा। ❑

लोकपाल बिल पर शुरू से ही सरकार का रवैया टालू है। जनाक्रोश को कम करने के लिए यूपीए सरकार ने लोकपाल बिल बनाने की बात मंजूर की थी। उसके बाद ही वह रामदेव के मुद्दे पर दमन पर उतर आई। इससे उसकी गम्भीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। पहले दिन से ही सरकार गलतबयानी व धोखा देने पर उतारू है। शातिर लोगों से अन्ना सदाशयता की उम्मीद क्यों पाले हैं? लोकपाल, भ्रष्टाचार और कालेधन पर सबको एकजुट होकर सरकार की मंशा को बदलना होगा।

आर्थिक संवृद्धि का अमानवीय चेहरा

हम देखते हैं कि हमारे आसपास ठेकेदारी व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले गार्ड, सफाई कर्मचारी आदि अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हैं और उनका वेतन भी गुजारे लायक वेतन से कहीं कम होता है। इन्हें मजदूरी के अतिरिक्त भत्ते आदि भी नहीं मिलते। दूसरी ओर वेतनभोगी स्थायी मजदूरों को बोनस, मकान किराया, भत्ता, दवा और इलाज के लिए खर्च, मुफ्त टेलीफोन, यातायात भत्ता आदि तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं या इन सुविधायों के बाजार मूल्य के आधार पर भरपाई होती है। आकस्मिक श्रमिकों की निम्न मजदूरी जिस मजदूरी पर आकस्मिक श्रमिकों का गुजारा चलता है, वह भी बहुत ही निम्न स्तर की होती है।

■ डॉ. अश्विनी महाजन

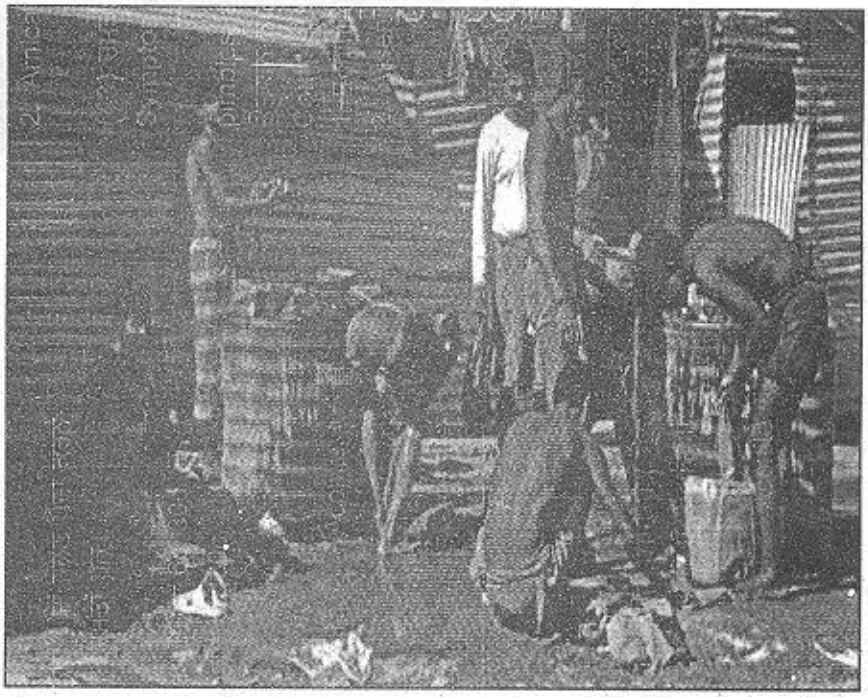

कुछ दिन पहले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने अपने 66वें सर्वेक्षण दौर की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में एक अत्यंत चिंताजनक बात सामने आई है रोजगार में बढ़ती आकस्मिकता या यो कहें कि अस्थिरता। नमूना सर्वेक्षण संगठन समय–समय पर रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2004–05 और 2009–10 के बीच आकस्मिक श्रमिकों की संख्या में 219 लाख की वृद्धि हुई। पिछले दौर की तुलना में यह वृद्धि काफी ज्यादा है। स्थायी यानी वेतन पाने वाले श्रमिकों की बात करें तो 2009–10 के दौर में यह वृद्धि पहले से आधी यानी मात्र 58 लाख की ही थी।

स्वरोजगार युक्त श्रमिकों जिसमें अधिकतर किसान, लघु और कुटीर उद्योगपति और व्यापारी आते हैं, की संख्या में 251 लाख की कमी दर्ज की गई है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जब आकस्मिक रोजगार वाले श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है तो रोजगार का स्तर घटता है और श्रमिकों के जीवन स्तर में कमी आती है। प्रतिशत आधार पर देखें तो पाते हैं कि 1993–94 में ग्रामीण क्षेत्रों में आकस्मिक रोजगार केवल 35.6 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 18.3 प्रतिशत था।

आमतौर पर माना जाता है कि आर्थिक संवृद्धि के साथ रोजगार भी बढ़ता है, लेकिन वर्तमान आर्थिक संवृद्धि अभी तक रोजगारविहीन आर्थिक संवृद्धि ही मानी जाती है, क्योंकि इसमें जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन रोजगार नहीं। पिछले पांच वर्षों में रोजगार में पहले से थोड़ी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली, लेकिन वह रोजगार स्तरीय रोजगार नहीं था। वास्तव में इस कालखंड में कम मजदूरी वाला आकस्मिक रोजगार ही बढ़ा।

2009–10 में यह ग्रामीण क्षेत्रों में 38.6 प्रतिशत पहुंच गया और शहरी क्षेत्रों में 17.5 प्रतिशत रहा। 2004–05 की तुलना में 2009–10 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आकस्मिकता वाला रोजगार तेजी से बढ़ा है।

गौरतलब है कि यह प्रतिशत 2004–05 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 35.0 और 15.1 प्रतिशत ही था।

नई आर्थिक नीति और भूमंडलीकरण के पैरोकार तो यह मानने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते कि इस आर्थिक नीति में कुछ गलत भी हो सकता है। वे तो लगातार बढ़ती आर्थिक संवृद्धि का दंभ भरते हैं। गौरतलब है कि रोजगार में घटियापन उन्हीं वर्षों में सबसे ज्यादा बढ़ा, जब आर्थिक संवृद्धि सबसे ज्यादा तेज थी। 2004–05 और 2009–10 में आर्थिक संवृद्धि की दर औसत रूप में 8 से 9 प्रतिशत रही, जबकि पूर्व के वर्षों में वह उससे कहीं कम थी। लेकिन पूर्व के वर्षों में आकस्मिक रोजगार घटा था।

आमतौर पर माना जाता है कि आर्थिक संवृद्धि के साथ रोजगार भी बढ़ता है, लेकिन वर्तमान आर्थिक संवृद्धि अभी तक रोजगारविहीन आर्थिक संवृद्धि ही मानी जाती है, क्योंकि इसमें जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन रोजगार नहीं। पिछले पांच वर्षों में रोजगार में पहले से थोड़ी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली, लेकिन वह रोजगार स्तरीय रोजगार नहीं था।

वास्तव में इस कालखंड में कम मजदूरी वाला आकस्मिक रोजगार ही बढ़ा। यदि हम इस आर्थिक संवृद्धि की तस्वीर देखते हैं तो इस बात का उत्तर साथ ही साथ मिल जाता है। इस आर्थिक संवृद्धि में हमारी आधी से अधिक आबादी, जो कृषि पर निर्भर करती है, की कोई भागीदारी नहीं थी।

जबकि अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में 8 से 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, कृषि की स्थिति सोचनीय ही बनी रही और उसमें मात्र शून्य से तीन प्रतिशत (औसतन 2 प्रतिशत) संवृद्धि दर्ज की गई। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के शेष क्षेत्रों में भी आर्थिक संवृद्धि संगठित क्षेत्रों और कारपोरेट क्षेत्र तक ही सीमित रही। पूंजीपतियों का लाभ और कुछ खास लोगों के वेतन बढ़े, लेकिन बहुसंख्यक लोगों के रोजगार का स्तर या तो बढ़ नहीं पाया या घट गया।

आकस्मिकता का मतलब आकस्मिक रोजगार यानी जहां श्रमिकों को काम में स्थायित्व और अन्य सुविधाओं का अभाव हो। ठेकेदारी व्यवस्था में काम करने वाले अधिकतर श्रमिक जो गार्ड, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर आदि के रूप काम करते हैं, वे सभी इसी श्रेणी में आते हैं। आकस्मिक रोजगार घटिया इसलिए माना जाता है, क्योंकि स्थायी कर्मचारियों की अपेक्षा आकस्मिक श्रमिकों की मजदूरी कम होती है और इसमें वृद्धि भी कम होती है।

हम देखते हैं कि हमारे आसपास ठेकेदारी व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले गार्ड, सफाई कर्मचारी आदि अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हैं और उनका वेतन भी गुजारे लायक वेतन से कहीं कम होता है। इन्हें मजदूरी के अतिरिक्त भत्ते आदि भी नहीं मिलते। दूसरी ओर वेतनभोगी स्थायी मजदूरों को बोनस, मकान किराया, भत्ता, दवा और

आकस्मिकता का मतलब आकस्मिक रोजगार यानी जहां श्रमिकों को काम में स्थायित्व और अन्य सुविधाओं का अभाव हो। ठेकेदारी व्यवस्था में काम करने वाले अधिकतर श्रमिक जो गार्ड, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर आदि के रूप काम करते हैं, वे सभी इसी श्रेणी में आते हैं। आकस्मिक रोजगार घटिया इसलिए माना जाता है, क्योंकि स्थायी कर्मचारियों की अपेक्षा आकस्मिक श्रमिकों की मजदूरी कम होती है और इसमें वृद्धि भी कम होती है।

इलाज के लिए खर्च, मुफ्त टेलीफोन, यातायात भत्ता, आदि तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं या इन सुविधायों के बाजार मूल्य के आधार पर भरपाई होती है। आकस्मिक श्रमिकों की निम्न मजदूरी जिस मजदूरी पर आकस्मिक श्रमिकों का गुजारा चलता है, वह भी बहुत ही निम्न स्तर की होती है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, तीन प्रकार के अस्थायी मजदूरों के लिए अलग–अलग मजदूरी की गणना की गई है। शहरी क्षेत्रों में स्थायी कर्मचारियों की मजदूरी औसत 365 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में यह 232 रुपये आंकी गई है, जबकि निजी क्षेत्र के कार्यों के लिए भाड़े पर लिए गए आकस्मिक मजदूरों की मजदूरी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 122 रुपये और 93 रुपये ही है।

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में यह मजदूरी पुरुषों के लिए 98 रुपये और महिलाओं के लिए 86 रुपये थी। रोजगार गारंटी योजना और सरकारी प्रकल्पों पर भाड़े पर लिए गए मजदूरों की मजदूरी क्रमशः पुरुषों और महिलाओं के लिए मात्र 91 रुपये और 87 रुपये आंकी गई है।

इसके अलावा यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि दिहाड़ी मजदूरों को वर्ष भर काम नहीं मिलता। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भी काम तो केवल 100 ही दिन मिल पाता है। शेष मजदूरों को तो उतना भी काम नसीब नहीं होता। वेतनभोगी मजदूरों से काम के दिनों में एक चौथाई से एक तिहाई ही मजदूरी और वास्तव में वर्ष भर में मात्र 100 दिनों से भी कम रोजगार की स्थिति देश में इन मजदूरों की बदतर स्थिति बयान करती है। नई आर्थिक नीति है दोषी इसके साथ मजदूरों में बढ़ती आकस्मिकता और अस्थायित्व अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

वास्तव में नई आर्थिक नीति के चलते कृषि, लघु और कुटीर उद्योगों में स्वरोजगार घट रहा है। इसके साथ सरकारों द्वारा किसानों की भूमि का जबरन अधिग्रहण, किसान से उसका परंपरागत रोजगार छिन रहा है। ऐसे में स्वरोजगार युक्त श्रमिकों में मात्र पांच वर्षों में 251 लाख की कमी और उन स्वरोजगार युक्त लोगों का आकस्मिक श्रमिक के रूप में बदलाव देश में आम मजदूर और किसान की बदहाली की ओर इशारा कर रहा है।

नई आर्थिक नीति के पैरोकारों को विचार करना होगा कि केवल जीडीपी आधरित आर्थिक संवृद्धि से आम आदमी के जीवन में सुधार नहीं हो सकता। लेकिन जब इस जीडीपी को बढ़ाने की कवायद में आम आदमी गरीबी की ओर जा रहा हो तो उस नीति का परित्याग कर जनोन्मुखी आर्थिक नीति बनानी होगी। कृषि, लघु उद्योग और अन्य स्वरोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों का विकास और बचाव ही एकमात्र उपाय है। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका साम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

अर्थव्यवस्था पर तिहरा दबाव

चाकलेट खाने से बच्चे का स्वास्थ बिगड़ रहा है। इस समस्या का समाधान च्यवनप्राश पर खर्च बढ़ाकर किया जा सकता है अथवा चाकलेट पर टैक्स लगाकर। चाकलेट पर टैक्स लगाने से दोहरा लाभ है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आय भी होगी। इसी प्रकार पूंजी सघन उद्योगों पर टैक्स लगाकर श्रम की मांग बढ़ानी चाहिए। दूसरा सुझाव है कि आम आदमी को राहत देने के नाम पर भारी भरकम कल्याणकारी माफिया को पोषित करने की जरूरत नहीं है। इस मद पर खर्च की जाने वाली रकम को सीधे जनता को नकद दे देना चाहिए।

■ डा. भरत झुनझुनवाला

वर्तमान में अर्थव्यवस्था तीन तरह से दबाव में है। विश्व बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। फरवरी में ये करीब 100 डॉलर प्रति बैरल थीं। आज 110 से 115 डालर पर पहुंच गई हैं। विश्व बाजार में तेल के दाम बढ़ने से सरकार को सब्सिडी अधिक देनी होती है, क्योंकि डीजल के घरेलू दाम न्यून निर्धारित किए गए हैं। इससे सरकार का घाटा बढ़ रहा है। दूसरे, अर्थव्यवस्था की विकास दर में भी हल्की गिरावट आ रही है। पूर्व की 9 प्रतिशत विकास दर के सामने वर्तमान अनुमान लगभग 8 प्रतिशत का है। विकास दर के गिरने से सरकार को टैक्स कम मिलता है। तीसरे, सरकार आम आदमी को राहत दिलाने के लिए भोजन सुरक्षा कानून बनाने जा रही है। इससे भी सब्सिडी खर्च बढ़ेगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था तीन तरफ से दबाव में है। ऐसे में सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ेगा। इस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार को नोट छापने पड़ेंगे। इससे महंगाई बढ़ेगी, जिसकी मार अंततः आम आदमी पर ही पड़ेगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए योजना आयोग तथा अन्य द्वारा पांच बिंदु की रणनीति सुझाई जा रही है।

पहला बिंदु है कि तेल, खाद्य सामग्री, एलपीजी गैस आदि पर दी जा रही सब्सिडी को घटाया जाए, परंतु ऐसा करने पर इन वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे और आम आदमी त्रस्त होगा। दूसरा बिंदु है कि सरकारी कर्मियों को दी जाने वाली पेंशन में कटौती की जाए। यह सुझाव सही है, किंतु क्रियान्वयन कठिन है। सरकार ने कर्मियों के वेतन और पेंशन में अप्रत्याशित वृद्धि इसलिए की है कि यह फौज सरकार के प्रति वफादार रहे और जरूरत पड़ने

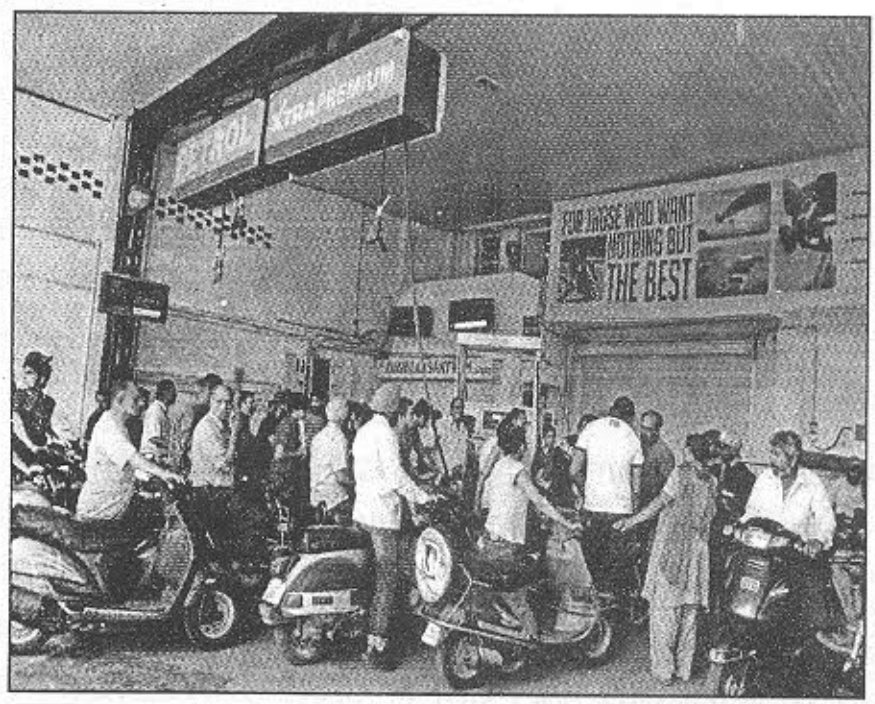

तीसरा सुझाव है कि डीजल के मूल्य में वृद्धि करके उस रकम से आम आदमी द्वारा खपत की जाने वाली वस्तुओं पर टैक्स में छूट देनी चाहिए। डीजल पर दी जा रही सब्सिडी भी अंततः आम आदमी से ही टैक्स के रूप में वसूली जाती है। यह व्यर्थ का प्रपंच है। डीजल सब्सिडी समाप्त करके उतनी रकम की छूट आम आदमी द्वारा खपत की जाने वाली वस्तुओं पर दी जानी चाहिए। तेल के बढ़ते मूल्य एवं विकास दर में गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था पहले ही दबाव में है।

पर आम आदमी का दमन करने से न चूके। मसलन रामदेव के शिविर पर रात में धावा बोलने वाले अनेक सिपाही सरकार के निर्णय से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ऊंचे वेतन और पेंशन के लोभ में उन्होंने अपनी अंतरात्मा को दबा दिया और रात में सोते हुए निरीह लोगों पर डंडे बरसाए। अतः सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कटौती करना अपनी नींव खोदने जैसा होगा।

तीसरा बिंदु रक्षा खर्च में कटौती करने का है। यह उपयुक्त नहीं हैं। मैंने कुछ वर्ष पूर्व अध्ययन किया था तो पाया कि जिन देशों के रक्षा खर्च ऊंचे थे उनकी आर्थिक विकास दर भी ऊंची थी। रक्षा खर्च में कटौती से आर्थिक विकास दर घटेगी।

चौथा बिंदु निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का है। बुनियादी सेवाओं में निवेश को इन्हें आमंत्रित किया जा सकता है। यह दिशा सही है। दिल्ली के एयरपोर्ट तथा अनेक हाईवे इसी विधा से बनाए गए हैं, परंतु दूसरे क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों की रुचि नहीं है, जैसे पानी के वितरण, ग्रामीण सड़कों के निर्माण, जंगल की रक्षा इत्यादि में। अतः निजी क्षेत्र की भागीदारी के बावजूद सरकारी निवेश में वृद्धि जरूरी होगी।

आयोग सरकारी कल्याणकारी खर्चें में वृद्धि की वकालत कर रहा है। आयोग की चिंता मात्र इन खर्चें के लिए पर्याप्त रकम जुटाने की है, परंतु रकम जुटाने में तमाम कठिनाइयां हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसके अलावा आयोग को समझना चाहिए कि जनता समझदार हो गई है। वह कल्याणकारी खर्चों से प्रभावित नहीं हो रही है. . करुणानिधि ने मुफ्त टेलीविजन सेट बांटे, लेकिन सत्ता खोनी पड़ी। कारण यह है कि सरकारी योजनाओं से जनता को लाभ कम ही पहुंचता है। सरकारी स्कूलों में बच्चे फेल होते हैं, मनरेगा के प्रधान कमीशन खाते हैं इत्यादि।

पांचवां बिंदु खपत टैक्स आरोपित करने का है। इस संदर्भ में सुझाव यह है कि उच्च वर्ग द्वारा खपत की जाने वाली वस्तुओं जैसे एयर कंडीशनर, कलर टीवी, लक्जरी कार आदि पर बिक्री कर के अलावा लग्जरी टैक्स लगा दिया जाए। यह सुझाव सही दिशा में है, परंतु इससे मिलने वाला राजस्व कम ही होगा। इससे मूल समस्या का समाधान नहीं होता है। मेरी समझ में योजना आयोग द्वारा सुझाए गए बिंदु मूल समस्या का समाधान हासिल करने में सफल नहीं हैं। योजना आयोग ने समस्या को सही ढंग से चिन्हित नहीं किया है।

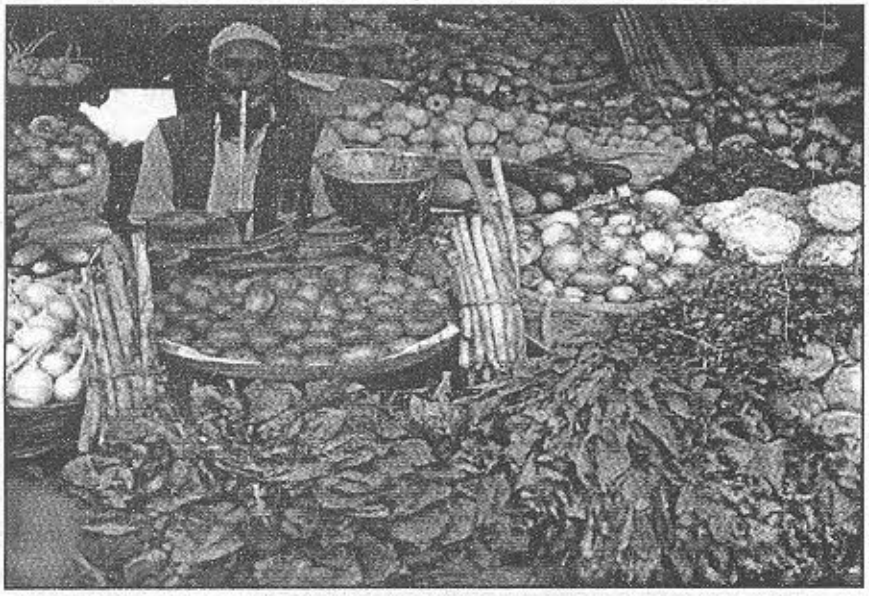

आयोग सरकारी कल्याणकारी खर्चें में वृद्धि की वकालत कर रहा है। आयोग की चिंता मात्र इन खर्चें के लिए पर्याप्त रकम जुटाने की है, परंतु रकम जुटाने में तमाम कठिनाइयां हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसके अलावा आयोग को समझना चाहिए कि जनता समझदार हो गई है। वह कल्याणकारी खर्चों से प्रभावित नहीं हो रही है। कुछ वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार को इसके बावजूद सत्ताच्युत होना पड़ा था कि उन्होंने तमाम कल्याणकारी योजनाएं चालू की थीं।

करुणानिधि ने मुफ्त टेलीविजन सेट बांटे, लेकिन सत्ता खोनी पड़ी। कारण यह है कि सरकारी योजनाओं से जनता को लाभ कम ही पहुंचता है। सरकारी स्कूलों में बच्चे फेल होते हैं, मनरेगा के प्रधान कमीशन खाते हैं इत्यादि। मूल समस्या इस प्रकार है। कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ाने के लिए रकम चाहिए। इससे सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ रहा है। घाटा बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है और आम आदमी त्रस्त हो रहा है। साथ ही

निवेशकों का भरोसा भी कम हो रहा है और आर्थिक विकास पर खतरा मंडराने लगा है। इस समस्या का हल छिटपुट कदम उठाने से नहीं निकलेगा, जैसा कि योजना आयोग इंगित कर रहा है। इस समस्या का हल सर्जरी से निकलेगा। पूंजी सघन उद्योगों एवं मशीनरी पर टैक्स लगा दिया जाए तो श्रम का उपयोग सहज ही ज्यादा होने लगेगा और आम आदमी को राहत मिल जाएगी। जैसे ट्रैक्टर पर टैक्स लगा दिया जाए तो हलवाहे का कारोबार स्वतः चल पड़ेगा और उसे मनरेगा की जरूरत नहीं रह जाएगी।

अथवा यूं समझें कि चाकलेट खाने से बच्चे का स्वास्थ बिगड़ रहा है। इस समस्या का समाधान च्यवनप्राश पर खर्च बढ़ाकर किया जा सकता है अथवा चाकलेट पर टैक्स लगाकर। चाकलेट पर टैक्स लगाने से दोहरा लाभ है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आय भी होगी। इसी प्रकार पूंजी सघन उद्योगों पर टैक्स लगाकर श्रम की मांग बढ़ानी चाहिए। दूसरा सुझाव है कि आम आदमी को राहत देने के नाम पर भारी भरकम कल्याणकारी माफिया को पोषित करने की जरूरत नहीं है। इस मद पर खर्च की जाने वाली रकम को सीधे जनता को नकद दे देना चाहिए।

मेरा आकलन है कि सभी सब्सिडी एवं कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त करके प्राप्त रकम को वितरित किया जाए तो प्रति परिवार प्रति माह 2500 रुपये दिए जा सकते हैं, जो मूल जरूरत के लिए पर्याप्त होंगे। तीसरा सुझाव है कि डीजल के मूल्य में वृद्धि करके उस रकम से आम आदमी द्वारा खपत की जाने वाली वस्तुओं पर टैक्स में छूट देनी चाहिए। डीजल पर दी जा रही सब्सिडी भी अंततः आम आदमी से ही टैक्स के रूप में वसूली जाती है। यह व्यर्थ का प्रपंच है। डीजल सब्सिडी समाप्त करके उतनी रकम की छूट आम आदमी द्वारा खपत की जाने वाली वस्तुओं पर दी जानी चाहिए। तेल के बढ़ते मूल्य एवं विकास दर में गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था पहले ही दबाव में है। कल्याणकारी खर्चे में वृद्धि से यह दबाव और बढ़ रहा है। इन खर्चे की सर्जरी करके आम आदमी की रक्षा करनी चाहिए। ❑

सदस्यता संबंधी सूचना

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि "स्वदेशी पत्रिका" के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है।

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	100/–	1000/–
अंग्रेजी	100/–	1000/–

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

पता : **स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22**

न पेट्रोल न डीजल और न रसोई गैस

खाओ अंगारे पीओ धुआं

संसदीय लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार केवल हानि–लाभ के आधार पर नहीं चल सकती। अगर सरकार विपरीत परिस्थितियों के कुप्रभाव से जनता की रक्षा नहीं कर सकती, उसके लिए राहत बनकर खड़ी नहीं हो सकती तो फिर ऐसी सरकार के होने का कोई मायने नहीं है। एक व्यापारी भी हानि–लाभ के आधार पर देश को चला लेगा। फिर हानि का आंकड़ा भी तेल कंपनियों का अपना है। वर्तमान बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के समर्थक विशेषज्ञ भी तेल कंपनियों के नौकरशाहों द्वारा दिए गए आंकड़ों को गलत बताते हैं।

■ अवधेश कुमार

केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी उबाल को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी और सरकार के प्रबंधनकर्ताओं को इसकी कोई परवाह है। जिस बेपरवाह तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं और सरकार व पार्टी उस पर जैसी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही है, वह आश्चर्यजनक है। डीजल, किरोसिन और रसोई गैस की कीमत बढ़ाने के बाद सरकार और कांग्रेस के रुख पर जरा नजर देखें। पेट्रोलिमय मंत्री जयपाल रेड्डी ने कहा कि मात्र 50 रुपये रसोई गैस पर बढ़ाए गए हैं। जयपाल रेड्डी के मुंह से मात्र शब्द निकलना असाधारण है। वे लंबे समय तक तीसरे मोर्चे के साथ जुड़े रहे और उन्हें समाजवादी धारा का नेता माना जाता है।

कांग्रेस में जयपाल रेड्डी के वर्तमान दौर के पूर्व गरीब तबके, पिछड़े, दलितों की दुरावस्थाओं पर उनका बयान देखेंगे तो आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि ये वाकई वही रेड्डी हैं। माहौल कैसे किसी व्यक्ति को बदलता है, यह इसका ज्वलंत उदाहरण है। ऐसी कोई पार्टी नहीं, जिसने सरकार के इस कदम का विरोध नहीं किया।

इनमें संप्रग के घटक दल भी शामिल हैं। किंतु सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस के नेताओं की पेशानी पर बल तक पड़ते नहीं दिख रहे। स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संपादकों से बातचीत में इसे जिस तरह सही ठहराया, उसके बाद शायद ही कुछ कहने की जरूरत रह जाती है। किंतु प्रधानमंत्री से इससे अलग कोई उम्मीद बेमानी थी। मूल्य वृद्धि के एक दिन बाद ही कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक थी, किंतु उसमें पार्टी ने इस पर चर्चा तक नहीं की। सामान्य पत्रकार वार्ता में इस बाबत प्रश्न पूछने पर कहा गया कि अपने मुख्यमंत्रियों को पेट्रोलियम पर लगने वाले कर एवं

डीजल, किरोसिन और रसोई गैस की कीमत बढ़ाने के बाद सरकार और कांग्रेस के रुख पर जरा नजर देखें। पेट्रोलिमय मंत्री जयपाल रेड्डी ने कहा कि मात्र 50 रुपये रसोई गैस पर बढ़ाए गए हैं। जयपाल रेड्डी के मुंह से मात्र शब्द निकलना असाधारण है। स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संपादकों से बातचीत में इसे जिस तरह सही ठहराया, उसके बाद शायद ही कुछ कहने की जरूरत रह जाती है।

अधिभार कम करने को कहा गया है। वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी सभी मुख्यमंत्रियों को इसके लिए पत्र लिखेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं। विरोधी पार्टियां चाहे जितना विरोध प्रदर्शन करती रहें, मीडिया की प्रतिक्रिया चाहे जितनी प्रतिकूल हों, कांग्रेस और सरकार ऐसे व्यवहार कर रही है, जैसे ये सब बनावटी हों और केवल राजनीतिक विरोधी उसके विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहे हैं।

इस बात पर मतभेद हो सकता है कि संप्रग की जगह दूसरे राजनीतिक समूह की सरकार होती या कांग्रेस की बजाय इसका नेतृत्व दूसरे दल के हाथों होता तो वे क्या करते, लेकिन आज का क्रूर सच यही है कि मनमोहन सिंह सरकार के पास हानि–लाभ के अपने एकपक्षीय आकलन के अनुसार महंगाई की मार से कराहते आम नागरिकों की जेब पर और भार डालने के अलावा बढ़े हुए अंतरराष्ट्रीय मूल्य से निपटने का कोई अन्य दृष्टिकोण दिखता ही नहीं। संसदीय लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार केवल हानि–लाभ के आधार पर नहीं चल सकती। अगर सरकार विपरीत परिस्थितियों के कुप्रभाव से जनता की रक्षा नहीं कर सकती, उसके लिए राहत बनकर खड़ी नहीं हो सकती तो फिर ऐसी सरकार के होने का कोई मायने नहीं है।

एक व्यापारी भी हानि–लाभ के आधार पर देश को चला लेगा। फिर हानि का आंकड़ा भी तेल कंपनियों का अपना

है। वर्तमान बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के समर्थक विशेषज्ञ भी तेल कंपनियों के नौकरशाहों द्वारा दिए गए आंकड़ों को गलत बताते हैं।

इस कदम के एक सप्ताह पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो एवं रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन करते समय ऐलान किया कि यह महंगाई के खिलाफ उसकी लड़ाई की रणनीति है। मार्च 2010 से रिजर्व बैंक ने 10वीं बार लगातार रेपो एवं रिवर्स रेपो दर में बढ़ोतरी की। खुद मुखर्जी ने उसके बाद कहा कि महंगाई सरकार की सबसे बड़ी चिंता है। वह यह कैसे भूल गई कि डीजल के मूल्य बढ़ने का अर्थ ढुलाई से आने वाले हर सामान का मूल्य बढ़ जाना है?

जिस सरकार के प्रधानमंत्री आर्थिक विशेषज्ञ हों, वित्तमंत्री के अलावा गृहमंत्री तक वित्त तथा वाणिज्य मंत्री रह चुके हों, उसमें ऐसे निर्णय का कारण ढूंढ़ना कठिन है। इससे यह आशंका बलवती होती है कि सरकार के अंदर वरिष्ठ मंत्रियों के बीच स्वाभाविक संवाद की स्थिति नहीं है और पार्टी तथा सरकार के बीच भी लगभग यही स्थिति है।

अगर सरकार के अंदर और सरकार व कांग्रेस के बीच स्वाभाविक संवाद होता तो अन्य रास्ते निकालने की कोशिश होती। सरकार पर नजर रखने वाले यह मानने को विवश हैं कि सरकार के अंदर के मतभदों और झगड़ों के कारण अनेक चुनौतियां होते हुए भी उपयुक्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। केवल तदर्थ तरीके से कामकाज चल रहा है। सरकार के स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण फैसले लंबित पड़े हैं। मानसून सत्र तक खिसका दिया जाता है और इसका कोई वाजिब कारण नहीं बताया जाता। प्रधानमंत्री की बातचीत में भी इसका समाधानपरक जवाब नहीं मिला।

किसी देश के लिए यह अत्यंत खतरनाक स्थिति है। भले प्रधानमंत्री ने

मार्च 2010 से रिजर्व बैंक ने 10वीं बार लगातार रेपो एवं रिवर्स रेपो दर में बढ़ोतरी की। खुद मुखर्जी ने उसके बाद कहा कि महंगाई सरकार की सबसे बड़ी चिंता है। वह यह कैसे भूल गई कि डीजल के मूल्य बढ़ने का अर्थ ढुलाई से आने वाले हर सामान का मूल्य बढ़ जाना है?

वित्त मंत्रालय में जासूसी की खबरों का बंद अध्याय कह दिया। खुद प्रणब मुखर्जी भी जासूसी की खबरों का खंडन कर चुके हैं, लेकिन 15–16 स्थानों पर चिपकाने वाले पदार्थों की उपस्थिति से देश में यह आशंका गहरी हुई है कि सरकार के अंदर सबकुछ ठीक–ठाक नहीं है और मंत्री ही मंत्री की जासूसी कर रहे हैं। मुखर्जी ने एक दिन पत्रकारों पर तमतमाते हुए प्रति प्रश्न कर दिया कि क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, पर इससे देश की आशंका का निवारण नहीं होता।

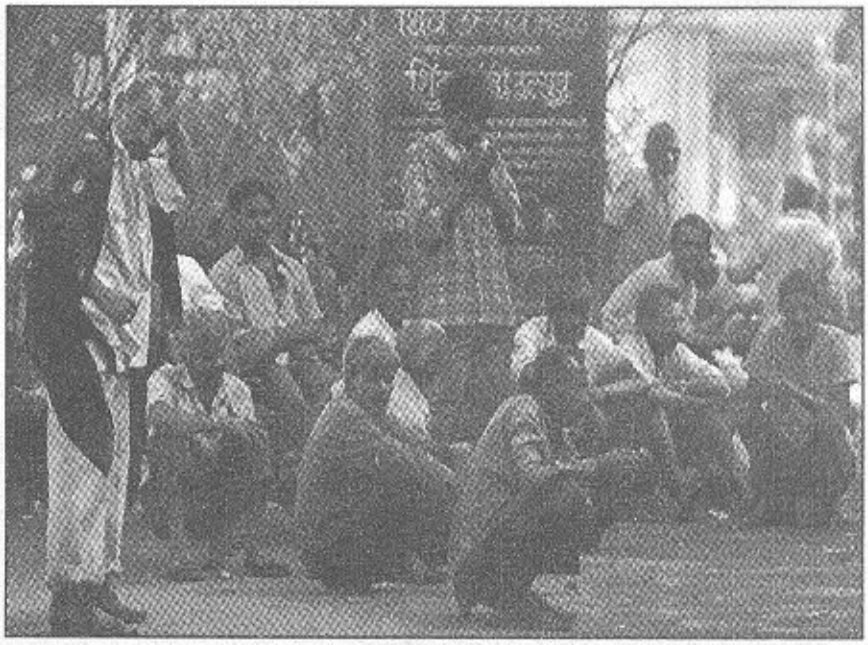

गृहमंत्री पी चिदंबरम ने भी कहा कि प्रणब दा से उनका कोई मतभेद नहीं है। वे हमारे वरिष्ठ हैं। क्या इससे देश की आशंकाओं का निवारण हो जाएगा? कायदे से ऐसी अनेक बातें उठ रहीं हैं, जिनका जवाब प्रधानमंत्री के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को देना चाहिए था। सोनिया कभी किसी विवाद पर सीधा पत्रकारों का सामना नहीं करतीं और न ही जनता के साथ सीधा संवाद की पहल करती हैं। प्रधानमंत्री ने भी काफी दबाव के बाद पत्रकारों से मिलने की शुरुआत की है। ऐसा लगता था, जैसे उन्होंने स्वयं को एक घेरे में बंद किया हुआ है।

कुछ दिनों पूर्व एक टीवी चैनल पर पूछे गए इससे संबंधित प्रश्न के जवाब में चिदंबरम ने कहा था कि इसका जवाब तो प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। मैं केवल यह कह सकता हूं कि यह किसी के काम करने की शैली है। यह कौन–सी शैली है? जनसंवाद से दूर रहना किसी नाराज नेता की शैली कैसे हो सकती है। अगर उन्होंने अपनी शैली में बदलाव किया है तो यह स्वागतयोग्य है, लेकिन यह ज्यादा खुला होना चाहिए।

वास्तव में सरकार के अंदर कायम मतभेद, मंत्रियों के बीच संवादहीनता और पार्टी तथा सरकार से बढ़ती दूरी का ही परिणाम था कि सरकार के मंत्री तो पहले बाबा रामदेव से बात करने गए। कुछ वायदे किए गए। स्वयं प्रधानमंत्री ने भी बाबा को पत्र लिखा, लेकिन एक दिन बाद ठीक इसके विपरीत बर्बर और सैन्य शासन की तरह कार्रवाई हुई। अन्ना हजारे से पहले सम्मानपूर्वक बातचीत और कुछ ही दिनों बाद पार्टी मंच से या अलग–अलग नेताओं द्वारा उन पर लांछन एवं तरह–तरह के विरोधी बयान।

यानी सरकार के कदमों में कोई तारतम्यता नहीं। इसके परिणाम स्वरूप अलग–अलग मंत्रियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं ने अपने अनुसार इसका अर्थ निकाला और प्रधानमंत्री की पत्रकार वार्ता से भी इस स्थिति का अंत नहीं हुआ है। मंत्रियों एवं नेताओं का कदम तथा वक्तव्य बार–बार लोकतांत्रिक सीमाओं को पार कर रहा है। इसमें जन भावनाओं की उपेक्षा, आंदोलनकारियों के प्रति हिकारत, बिना राजनीतिक प्रभाव का आकलन किए सरकार के निर्णय आदि शामिल हैं।

भले सारे परिणाम सीधे तौर पर दिखाई नहीं दें, लेकिन देश के लिए यह स्थिति अनर्थकारी है। इसमें बदलाव अपरिहार्य है। अगर कांग्रेस नेतृत्व एवं सरकार के नेतृत्वकर्ताओं के रवैये में बदलाव नहीं आया तो उसे प्रतिकूल राजनीतिक परिणाम भुगतना ही होगा, लेकिन तब तक देश की अपूरणीय क्षति हो चुकी होगी।

निश्चय ही देश इसका परिणाम भुगत रहा है। भले सारे परिणाम सीधे तौर पर दिखाई नहीं दें, लेकिन देश के लिए यह स्थिति अनर्थकारी है। इसमें बदलाव अपरिहार्य है। अगर कांग्रेस नेतृत्व एवं सरकार के नेतृत्वकर्ताओं के रवैये में बदलाव नहीं आया तो उसे प्रतिकूल राजनीतिक परिणाम भुगतना ही होगा, लेकिन तब तक देश की अपूरणीय क्षति हो चुकी होगी। ❑

अमरीका का असली चेहरा

डब्ल्यूटीओ में तय हुआ कि विकसित देश अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी कम करेंगे। अमरीका ने ठीक उल्टा किया। वह किसानों को भारी सब्सिडी दे रहा है, नतीजन, तीसरी दुनिया के देश कृषि के अंतरराष्ट्रीय बाजार में टिक नहीं पा रहे। 10 साल से डब्लूटीओ का दोहा चक्र चल रहा है। विकासशील देश कह रहे हैं– भाईजान, खेती की सब्सिडी क्यों नहीं कम करते हो! जवाब मिलता है – पहले हमारे गैर कृषि – यानी उद्योग–सेवा के लिए अपना बाजार खोल दो तब सोचेंगे।

■ डॉ. बनवारी लाल शर्मा

बहुत कम लोग इसे याद रख पा रहे होंगे कि भारत में भूमंडलीकरण के बीस साल पूरे होने जा रहे हैं. आगामी 24 जुलाई को भारत में नव उदारवादी अर्थव्यवस्था की शुरूआत के बीस साल पूरे हो जाएंगे। 24 जुलाई 1991 को ही अपने बजटीय भाषण में तत्कालीन वित्तमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत को भूमंडल के बाजार से जोड़ने का ऐलान किया था। नेहरूवादी समाजवाद की समाधि पर बाजारवादी व्यवस्था के आगाज की जो घोषणा की गयी उसके बीस साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर हमें बहुत कुछ याद करने की जरूरत है. बहुत विस्तार में बात करने की जरूरत है. . . .

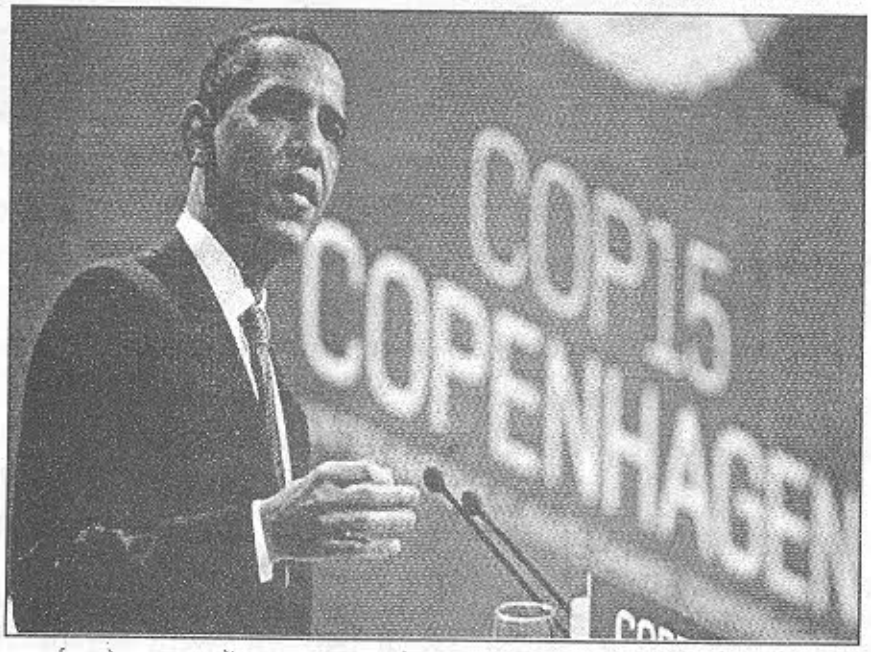

पिछले बीस साल में दुनिया के देश समुदाय में भारत का चेहरा बदल गया है। आजादी के बाद और बीस साल पहले तक भारत का दुनिया में शानदार स्थान था। दो लड़ाकू गुटों – अमरीका और सोवियत संघ से अलग दुनिया के कोई 100 गुट निरपेक्ष देशों का अगुआ देश भारत था और इस नाते उसका बड़ा सम्मान था। दुनिया में जहां भी झगड़े होते थे, भारत की आवाज सुनी जाती थी। अहिंसात्मक आन्दोलन करके आजादी पाने के कारण, गांधीजी के नाम से विकासशील देश भारत की तरफ मार्गदर्शन के लिए देखते थे। अमरीका, यूरोप, रूस, जापान जैसे विकसित देशों की दुनिया को लूटने की चालबाजियों से भारत अन्य गुट निरपेक्ष देशों के साथ मिलकर, उनका नेतृत्व संभालकर टक्कर दिया करता था।

पिछले बीस साल में दुनिया के देश समुदाय में भारत का चेहरा बदल गया है। आजादी के बाद और बीस साल पहले तक भारत का दुनिया में शानदार स्थान था। दो लड़ाकू गुटों – अमरीका और सोवियत संघ से अलग दुनिया के कोई 100 गुट निरपेक्ष देशों का अगुआ देश भारत था और इस नाते उसका बड़ा सम्मान था। दुनिया में जहां भी झगड़े होते थे, भारत की आवाज सुनी जाती थी।

गैट के आठवें चक्र – यूरुग्वे चक्र में भारत ने 32 विकासशील देशों का समूह बनाकर अमरीका, यूरोप, जापान द्वारा बौद्धिक सम्पदा, पूंजी निवेश, सेवा और खेती जेसे मुद्दों को व्यापार वार्ता में लाने का घोर विरोध किया था और तीन साल तक बात आगे नहीं बढ़ने दी थी।

उसी भारत को आज तीसरी दुनिया के देश हिकारत की नजर से देखते हैं। ऐसा कैसे हुआ? 1989 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमरीका ने भारत को

अपने गुट में मिलाने की चाल चली। एक तो, उसे भारत का बड़ा बाजार चाहिए था और दूसरे, उससे टक्कर लेने की तैयारी कर रहे देश चीन के बीच एक 'बफर जोन' चाहिए था अमरीका को जो भारत ही हो सकता था। बड़ी चतुराई से अमरीका और यूरोप की मुट्ठी में बंधे विश्व बैंक और मुद्राकोष के भारतीय नौकरशाहों को भारत की राजनीति में घुसाया। डॉ. मनमोहन सिंह से यह कवायद शुरू हुई। 1992 में केन्द्र सरकार में वित्तमंत्री बनकर विश्व बैंक के नौकर डॉ. मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को (और आगे चलकर राजनीति को भी) अमरीका और यूरोप की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोल दिया। उन्होंने छोड़ दिया गांधी का स्वावलंबन का रास्ता, छोड़ दिया गुट निरपेक्ष देश का नेतृत्व और डाल दिया भारत को अमरीकी गुट में। आज भारत गुट निरपेक्ष देश नहीं है, वह बाकायदा अमरीकी गुट का सदस्य है। कृषि, सेवा, शिक्षा, उद्योग ही नहीं, सुरक्षा के क्षेत्र में अमरीकी दखलंदाजी बढ़ रही है।

जरा हम देखें कि वह कैसा अमरीका है जिसका पिछलग्गू बनने में इस देश की सरकार, उद्यमी और कुछ बुद्धिजीवी पगला गये हैं। डॉ. मनमोहन सिंह ने केवल एक बार प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही है। वह कब? कहा– 'अगर अमरीका के साथ परमाणु सौदा संसद से पास न होता तो मैं त्याग पत्र दे देता'। वफादारी की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है?

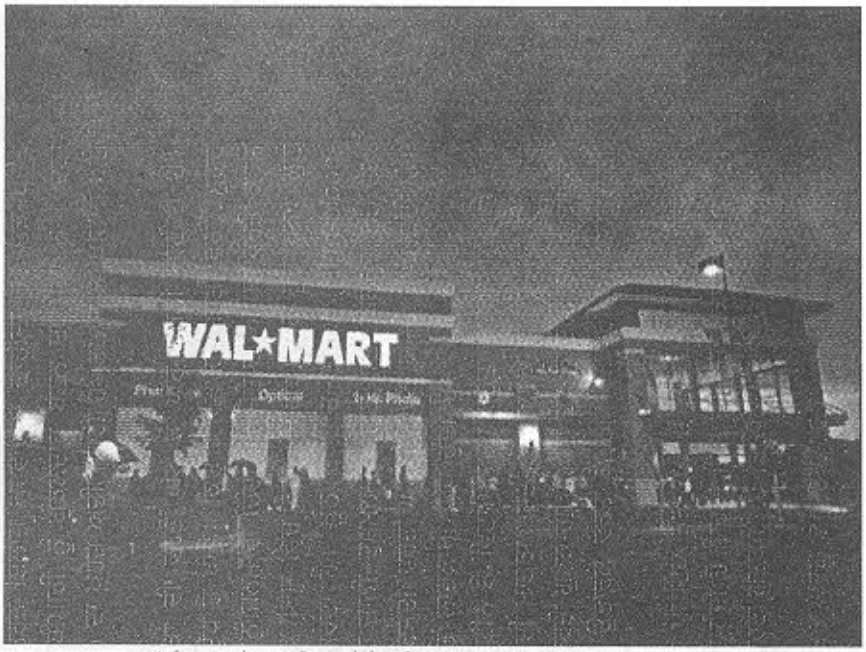

इस अमरीका की कुछ खास बातें ये हैं :

(1) **अमरीका दुनिया में दादागीरी करने वाला पहला देश है :** वियतनाम से फ्रांसीसियों के बाहर निकलने के बाद वहां घुस गया, अपनी फौजें बिछा दी। बहाना बनाया, इस देश को कम्युनिस्टों से बचाना है। 7–8 साल में उस छोटे से देश को इस 'महान' देश ने ध्वस्त कर दिया और फिर मुँह की खाकर, पूँछ दबाकर बाहर भागना पड़ा। वही कुकर्म इसने अफगानिस्तान में किया है। 26/11 की घटना के लिए ओसामा को जिम्मेदार ठहराकर उसे खोजने निकल पड़ा अफगानिस्तान में। 10 साल में उस छोटे देश का, जो उससे पहले 24 साल तक अमरीका और सोवियत संघ की कुश्ती का मैदान बना रहा था, तबाह कर दिया। ओसामा अफगानिस्तान में नहीं, अमरीका के दोस्त देश पाकिस्तान में मिला। वियतनाम की तरह अफगानिस्तान में भी मुँह की खाकर ओबामा कुछ अमरीकी फौजें वहां से हटा रहा है। क्या किया उसने 10 साल में? अपने 1551 सैनिक मरवाये, 443 अरब डॉलर फूँके, हजारों बेकसूर अफगानियों को मारा और झक मारकर तालिबानियों से बातचीत करने की पहल की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय मामलों में अमरीका का व्यवहार एक शराबी गुण्डे की तरह रहा है।

(2) दुनिया का सबसे बड़ा

1992 में केन्द्र सरकार में वित्तमंत्री बनकर विश्व बैंक के नौकर डॉ. मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को (और आगे चलकर राजनीति को भी) अमरीका और यूरोप की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोल दिया। उन्होंने छोड़ दिया गांधी का स्वावलंबन का रास्ता, छोड़ दिया गुट निरपेक्ष देश का नेतृत्व और डाल दिया भारत को अमरीकी गुट में। आज भारत गुट निरपेक्ष देश नहीं है, वह बाकायदा अमरीकी गुट का सदस्य है। कृषि, सेवा, शिक्षा, उद्योग ही नहीं, सुरक्षा के क्षेत्र में अमरीकी दखलंदाजी बढ़ रही है।

भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अमरीका को स्वर्ग मानते हैं, वहां अपने बेटे–बेटियों को पढ़ाने, नौकरी कराने और बुढ़ापे में वहीं आखिरी वक्त काटने का मौका मिलने से जीवन को धन्य मानते हैं। आज अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। ताजे आँकड़ों के अनुसार अमरीका पर उसके जीडीपी का 99.5 फीसदी कर्ज लदा है।

कर्जदार देश : भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अमरीका को स्वर्ग मानते हैं, वहां अपने बेटे–बेटियों को पढ़ाने, नौकरी कराने और बुढ़ापे में वहीं आखिरी वक्त काटने का मौका मिलने से जीवन को धन्य मानते हैं। यह देश दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। ताजे आँकड़ों के अनुसार अमरीका पर उसके जीडीपी का 99.5 फीसदी कर्ज लदा है।

(3) **टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की पोल खुल गयी :** कहा जाता है कि अमरीका टेक्नोलाजी और मैनेजमेंट में दुनिया का गुरू है। अमरीका जब मंदी आयी, उससे पोल खुल गयी। लेहमन ब्रदर्स जैसी बैंके और जनरल मोटर्स जैसे उद्योग घराने दिवालिया हो गये। 300 से ज्यादा बैंकों पर ताले पड़ गये हैं, अरबों रुपया आमजन का डूब गया है, बेरोजगारी पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। निजी कंपनियों और बैंकों की वकालत करने वाले देश की सरकार ने अरबों डालर इन निजी संस्थानों को बचाने के लिए लोगों के धन से दिये।

(4) **दुनिया का सबसे बड़ा झूठा देश :** लिखित रूप से हस्ताक्षर किये गये समझौतों को तोड़ने में अमरीका का कोई सानी नहीं। अनेक उदाहरण हैं, यहां केवल दो का उल्लेख पर्याप्त है। पृथ्वी और उसके पर्यावरण को बचाने के लिए 1992 में रियो सम्मेलन हुआ। उसमें कार्बन डाईआक्साइड गैस कम करने के लिए एक समिति बनी जिसने 5 साल मेहनत करके क्योटो प्रोटोकॉल बनाया जिसमें अमरीका अपने देश में 7 फीसदी कार्बनडाई आक्साइड का सृजन कम करने के लिए राजी हुआ। अमरीकी प्रतिनिधि ने क्योटो प्रोटोकॉल पर बाकायदा दस्तखत किये। पर यह देश मुकर गया। बोला, नहीं करते हैं कम। दूसरा उदाहरण, डब्ल्यूटीओ में तय हुआ कि विकसित देश अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी कम करेंगे। अमरीका ने ठीक उल्टा किया। वह किसानों को भारी सब्सिडी दे रहा है, नतीजन, तीसरी दुनिया के देश कृषि के अंतरर ट्रीय बाजार में टिक नहीं पा रहे। 10 साल से डब्लूटीओ को दोहा चक्र चल रहा है। विकासशील देश कह रहे हैं– भाईजान, खेती की सब्सिडी क्यों नहीं कम करते हो! जवाब मिलता है – पहले हमारे गैर कृषि – यानी उद्योग–सेवा के लिए अपना बाजार खोल दो तब सोचेंगे।

(5) **दुनिया का सबसे बड़ा नैतिक पतन वाला देश :** 1996 में अमरीका में एक आयोग का गठन हुआ, नैतिक पतन के कारण और उनका निदान खोजने के लिए। कहा गया – अमरीका दुनिया में चोटी पर है – सेक्स और हिंसा में, तलाक दर में, सिंगल पेरेंट परिवार में, अश्लील साहित्य के उत्पादन और उपभोग में, यह सूची लम्बी है।

सवाल यह है कि भारत की सरकार ऐसे घटिया देश के गुट में क्यों शामिल हो रही है? क्या उसकी दादागीरी से डर गयी है? इसका जवाब इस देश के लोग देंगे। अमरीका (और उसके गुट के अन्य देशों) की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश के बाहर खदेड़ देंगे, एक भी परमाणु प्लांट नहीं लगने देंगे तथा अन्य अमरीक अड्डों को समाप्त करेंगे। ❑

अफगानिस्तान में भारत की भूमिका

कजाकिस्तान में संपन्न हुए शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भी काफी उदारता के स्वर फूटे हैं। रूस और चीन चाहते हैं कि भारत, पाकिस्तान, ईरान और मंगोलिया भी इसके सदस्य बन जाएं। अफगानिस्तान तो लगभग बन ही गया है। इस नई पहल का संकेत स्पष्ट है। रूस और चीन इस संगठन को मात्र अमेरिका विरोधी मोर्चा नहीं बनाना चाहते। वे चाहते हैं कि एशिया के सभी राष्ट्र इस संगठन के तहत ऐसी भूमिका निभाएं, जिससे अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता तो स्थापित हो ही, परस्पर सहयोग के आयाम भी खुलें।

■ डा. वेदप्रताप वैदिक

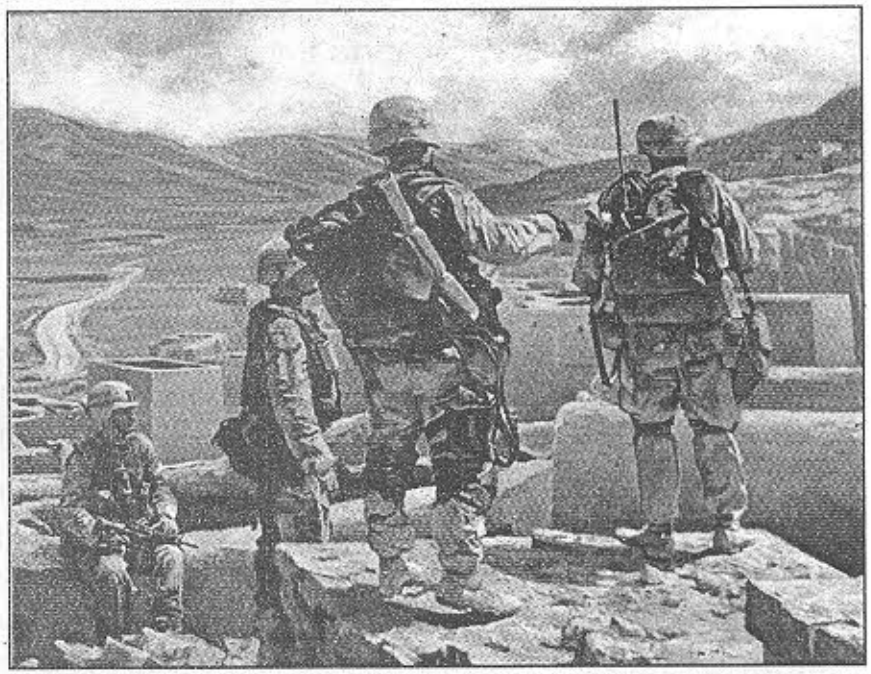

बराक ओबामा ने घोषणा की है कि जुलाई 2011 महीने से अमेरिकी फौजों की अफगानिस्तान से वापसी शुरू हो जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि पिछले दस वर्षों से दक्षिण एशिया में जो राजनीति चल रही है, उसमें कुछ बुनियादी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। ये बदलाव क्या–क्या हो सकते हैं?

सबसे पहला बदलाव तो यह हो सकता है कि अफगानिस्तान में अराजकता फैल जाए। अब तक अफगानिस्तान में करजई सरकार इसीलिए टिकी रही, क्योंकि विदेशी सेनाएं तालिबान और अल कायदा से लड़ती रहीं। यदि काबुल में अंतरराष्ट्रीय सेनाएं नहीं होतीं तो करजई सरकार उसी तरह गिर जाती, जैसे नजीबुल्लाह, रब्बानी और मुल्ला उमर की सरकारें गिरी थीं। इस खतरे के प्रति ओबामा प्रशासन सतर्क जरूर है, लेकिन उसने अभी तक कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम नहीं किया है कि करजई सरकार अपने दम पर जिहादियों का मुकाबला कर सके। ऐसी स्थिति में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेनाएं अफगानिस्तान से केवल कुछ हद तक ही हटेंगी। पूरी तरह नहीं हटेगी।

रूस, चीन, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान जैसे देशों को यह चिंता है कि यदि अमेरिका अफगानिस्तान में उसी तरह से टिक गया, जैसे कि वह यूरोपीय देशों में 65 साल से टिका है, तो उनके अपने हित प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। अपने फौजी अड्डों से अमेरिका इन देशों के आंतरिक मामलों में तो सीधा हस्तक्षेप कर ही सकता है, वह जासूसी जाल भी आसानी से बिछा सकता है। वह चाहे तो अंदरूनी बगावतें भी भड़का सकता है।

स्थायी सैनिक अड्डे

ऐसी खबरें भी हैं कि अमेरिका चाहे अपने सैनिकों की संख्या घटा दे, लेकिन अफगानिस्तान के पांच–छह सामरिक स्थानों पर अपने स्थायी सैनिक अड्डे बनाए रखेगा। इस खबर से पास–पड़ोस के सभी देश चिंतित हैं। पाकिस्तान को चिंता यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान का स्थायी संरक्षक बन गया तो उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। वह अफगानिस्तान पर अपनी दादागीरी कैसे चला पाएगा? भारत के विरुद्ध उसे वह अपना सामरिक पिछवाड़ा कैसे बना पाएगा?

रूस, चीन, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान जैसे देशों को यह चिंता है कि यदि अमेरिका

अफगानिस्तान में उसी तरह से टिक गया, जैसे कि वह यूरोपीय देशों में 65 साल से टिका है, तो उनके अपने हित प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। अपने फौजी अड्डों से अमेरिका इन देशों के आंतरिक मामलों में तो सीधा हस्तक्षेप कर ही सकता है, वह जासूसी जाल भी आसानी से बिछा सकता है। वह चाहे तो अंदरूनी बगावतें भी भड़का सकता है। इसके अलावा अफगानिस्तान की सामरिक स्थिति या उसके खनिजों से यदि किसी पड़ोसी देश को कोई लाभ होता होगा तो उसकी चाबी भी अमेरिका के हाथ में ही होगी। सारे पड़ोसी राष्ट्र मिलकर भी अमेरिका के इस प्रभुत्व को चुनौती नहीं दे पाएंगे।

कौन देगा सुरक्षा की गारंटी

इसलिए नहीं दे पाएंगे कि क्योंकि ये सब राष्ट्र मिलकर भी अफगानिस्तान को उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। रूस तो पहले ही अफगानिस्तान में झुलस चुका है। चीन अपने दूरगामी हितों को ध्यान में रखते हुए यह रिस्क नहीं लेना चाहेगा। पाकिस्तान को पता है कि हर अफगान उसके इरादों के बारे में कितना आशंकित रहता है। पाकिस्तान के साथ तीन–तीन बार अफगानिस्तान के युद्ध की नौबत तक आ चुकी है। ईरान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान की इतनी सैन्य हैसियत नहीं कि वे किसी राष्ट्र को फौजी सुरक्षा दे सकें। ऐसी हालत में भारत एकमात्र राष्ट्र है, जो अफगान फौज को अपने पांव पर खड़ा कर सकता है। भारत चाहे तो साल भर में वह पांच लाख अफगान जवानों को प्रशिक्षण देकर ऐसी फौज खड़ी कर सकता है, जो आंतरिक और बाहरी दोनों खतरों का मुकाबला कर सकती है। लेकिन क्या अमेरिका इस विकल्प के लिए तैयार होगा?

यदि अमेरिका इस विकल्प के लिए तैयार हो जाए तो अफगानिस्तान संपूर्ण एशिया की शांति और समृद्धि का केंद्र बन सकता है। अफगानिस्तान से अमेरिका के हटते ही तालिबान के बने रहने का तर्क ध्वस्त हो जाएगा। तालिबान का मुख्य मुद्दा यही है कि वे अफगान मातृभूमि को विदेशी कब्जे से मुक्त करवाना चाहते हैं। यदि काबुल में ऐसी सरकार कायम हो जाए, जो सचमुच संप्रभु हो और जन समर्थित हो तो फिर वहां अशांति और हिंसा रह ही नहीं सकती। ऐसी स्थिति में मध्य एशिया की अपार खनिज संपदा भारत, चीन, रूस और अमेरिका जैसे समर्थ राष्ट्रों को सहज सुलभ हो जाएगी। वे खुद तो अपार समृद्धि के स्वामी बनेंगे और वे इन मुस्लिम राष्ट्रों को भी मालामाल कर देंगे। अफगानिस्तान संपूर्ण एशिया की समृद्धि का चौराहा बन जाएगा।

भारत एकमात्र राष्ट्र है, जो अफगान फौज को अपने पांव पर खड़ा कर सकता है। भारत चाहे तो साल भर में वह पांच लाख अफगान जवानों को प्रशिक्षण देकर ऐसी फौज खड़ी कर सकता है, जो आंतरिक और बाहरी दोनों खतरों का मुकाबला कर सकती है। लेकिन क्या अमेरिका इस विकल्प के लिए तैयार होगा?

किनारा करे अमेरिका

इसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई की ताजा इस्लामाबाद यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और पारगमन की समस्त बाधाएं दूर हो गईं। अब अफगान माल पाकिस्तान होता हुआ वाघा बार्डर तक यानी भारत तक आ सकेगा। यह ठीक है कि पाकिस्तान अफगानी ट्रकों को भारत की सीमा में नहीं घुसने देगा। इसके बावजूद अफगान–भारत व्यापार बढ़ेगा। उधर पाकिस्तानी माल अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया के सभी गणतंत्रों में जा सकेगा। जिस दिन पाकिस्तान इस रास्ते को भारत के लिए खोल देगा, सभी देशों के वारे–न्यारे हो जाएंगे। आखिर पाकिस्तान कब तक इस प्रलोभन से बचा रहेगा? यदि अमेरिका सचमुच दक्षिण एशिया से थोड़ा किनारा कर ले और पाकिस्तान के मुंह में लड्डू रखना बंद कर दे तो पाकिस्तान अपने आप यह रास्ता भारत के लिए खोल देगा।

असल में अफगानिस्तान होकर मध्य एशिया में जाने वाले इन मार्गों के खुलने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी कजाकिस्तान में संपन्न हुए शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भी काफी उदारता के स्वर फूटे हैं। रूस और चीन चाहते हैं कि भारत, पाकिस्तान, ईरान और मंगोलिया भी इसके सदस्य बन जाएं। अफगानिस्तान तो लगभग बन ही गया है। इस नई पहल का संकेत स्पष्ट है। रूस और चीन इस संगठन को मात्र अमेरिका विरोधी मोर्चा नहीं बनाना चाहते। वे चाहते हैं कि एशिया के सभी राष्ट्र इस संगठन के तहत ऐसी भूमिका निभाएं, जिससे अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता तो स्थापित हो ही, परस्पर सहयोग के आयाम भी खुलें। सैकड़ों वर्ष पुराना चीन से यूरोप तक जाने वाला रेशम पथ (सिल्क रूट) फिर से हरा–भरा हो और यह एशिया का अछूता और अविकसित भूखंड विश्व–समृद्धि का केंद्र बन जाए। 'शंघाई राष्ट्रों' का यह सपना तभी पूरा हो सकता है, जबकि अमेरिका थोड़ी दूरंदेशी और उदारता का परिचय दे। ❑

परमाणु करार के दुष्परिणाम

मनमोहन सिंह द्वारा देश को दिए गए तमाम आश्वासनों के बावजूद अब राष्ट्र अलग–थलग पड़ता नजर आ रहा है और परिणाम हमारे अनुकूल नहीं हैं। इसका कारण यह है कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी संवर्द्धित और परिष्कृत उपकरणों के हस्तांतरण पर अब रोक लगा रहा है जो कि अमेरिका के हाइड एक्ट की शेष शर्तों को पूरा करने वाला है। इससे साफ है कि भारत द्वारा किया गया परमाणु समझौता अब महंगा पड़ रहा है और जिन लाभों को इसके माध्यम से बढ़ा–चढ़ाकर मिलने की बात कही गई थी वे अभी तक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं हैं।

■ ब्रह्मा चेलानी

अमेरिका के साथ तीन से भी अधिक वर्षों तक परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता की प्रक्रिया चली थी और प्रधानमंत्री ने पूरे देश को आश्वस्त किया था कि वह इस समझौते को अंतिम स्वीकृति तभी देंगे जब इसके समर्थन में व्यापक राजनीतिक सहमति हासिल कर ली जाएगी। वह कहते रहे कि एक बार प्रक्रिया पूरी होने दीजिए इसके बाद मैं इसे संसद के सामने लाऊंगा और इस पर सदन की स्वीकृति ली जाएगी।

इतना सब कहने के बावजूद वह संसद को पूरी तरह अलग–थलग रखते हुए आगे बढ़ गए। देश इस बात का प्रत्यक्ष गवाह है कि प्रधानमंत्री ने राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश करने की बजाय एकसूत्रीय कार्यक्रम के तहत किसी भी कीमत पर समझौते को आगे बढ़ाया। इस तरह का उत्साह दिखाने का परिणाम यह हुआ कि भारत को समझौते से जो लाभ मिल सकता था वह न केवल खोना पड़ा, बल्कि अमेरिका को और अधिक कठिन शर्तें थोपने का मौका मिल गया।

मनमोहन सिंह द्वारा देश को दिए गए तमाम आश्वासनों के बावजूद अब राष्ट्र अलग–थलग पड़ता नजर आ रहा है और परिणाम हमारे अनुकूल नहीं हैं। इसका कारण यह है कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी संवर्द्धित और परिष्कृत उपकरणों के हस्तांतरण पर अब रोक लगा रहा है जो कि अमेरिका के हाइड एक्ट की शेष शर्तों को पूरा करने वाला है। इससे साफ है कि भारत द्वारा किया गया परमाणु समझौता अब महंगा पड़ रहा है और जिन लाभों को इसके माध्यम से बढ़ा–चढ़ाकर मिलने की बात कही गई थी वे अभी तक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं हैं।

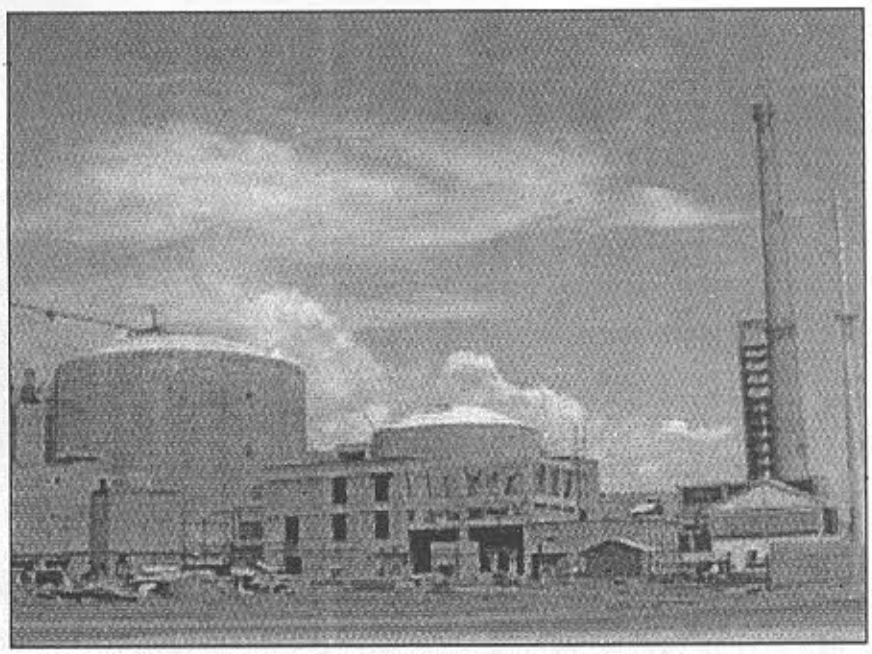

अमेरिका के सहयोग से निर्मित तारापुर परमाणु संयत्र के मामले में ईधन आपूर्ति को लेकर खट्टा अनुभव मिलने के बावजूद भारत नए परमाणु समझौते में अमेरिका से परमाणु ईंधन की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए कानूनी रूप से आश्वासन पाने में नाकामयाब रहा है। यदि 1970 की तरह अमेरिका एक बार फिर एकतरफा कार्रवाई करते हुए सहयोग को खत्म करता है तो हमारे पास इससे बचने का कोई भी उपाय नहीं है।

अमेरिका के सहयोग से निर्मित तारापुर परमाणु संयत्र के मामले में ईंधन

आपूर्ति को लेकर खट्टा अनुभव मिलने के बावजूद भारत नए परमाणु समझौते में अमेरिका से परमाणु ईंधन की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए कानूनी रूप से आश्वासन पाने में नाकामयाब रहा है। यदि 1970 की तरह अमेरिका एक बार फिर एकतरफा कार्रवाई करते हुए सहयोग को खत्म करता है तो हमारे पास इससे बचने का कोई भी उपाय नहीं है।

वर्ष 2008 में यह प्रचार किया गया था कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह देशों ने भारत को स्वच्छ और अबाधित परमाणु ईंधन आपूर्ति की छूट दे दी है, लेकिन यह एक भ्रम था। राजनीतिक रूप से चौतरफा घिरी मनमोहन सिंह सरकार ने जनता में अपनी छवि बचाए रखने के लिए इस प्रचार का सहारा लिया था। वास्तव में अमेरिका ने तभी यह साफ कर दिया था कि यह छूट सशर्त होगी। यह छूट तभी तक मिलेगी जब तक कि शर्तों का पालन होता रहेगा। उस समय भी भारतीय कूटनीतिज्ञों ने कहा था कि परमाणु परीक्षण और संवर्द्धित व परिष्कृत परमाणु तकनीक के हस्तांतरण संबंधी बातें साफ नहीं हैं, जिस बारे में प्रधानमंत्री को स्थिति साफ करनी चाहिए।

इस संदर्भ में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह देशों में परमाणु प्रसार को लेकर कुछ सवाल भी उभरे थे। बावजूद इसके नई दिल्ली के लिए छूट को लेकर प्रयुक्त भाषा को राजनीतिक रूप से स्वादिष्ट बनाकर पेश किया गया। हालांकि इसकी आधारभूत शर्तें हाइड एक्ट के मुताबिक ही घालमेल की गईं थीं।

भारत के साथ खुले नागरिक परमाणु व्यापार के निर्णय में छूट की शर्तों को कई परतों में बांधा गया था, जिनमें से कुछ स्पष्ट थीं तो कुछ अस्पष्ट। हालांकि इसमें भारतीय परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध को एनएसजी के दिशानिर्देश से संदर्भित किया गया था। इसमें अनुच्छेद 16 के तहत परमाणु परीक्षण के परिणामों को शामिल किया गया है, जबकि इस गाइडलाइन के अनुच्छेद 6 और 7 में संवेदनशील तकनीक से जुड़ी शर्तों को शामिल किया गया है।

यह अनुच्छेद एक अल्पकालिक कदम के तौर पर संवर्द्धित और परिष्कृत उपकरणों व संवेदनशील तकनीक के व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए लागू होते हैं जब तक कि एनएसजी इन पर औपचारिक प्रतिबंध नहीं लगा देता। पिछले सप्ताह औपचारिक प्रतिबंध की घोषणा कर दी गई। इसका प्रभाव भारत पर पड़ना तय है, क्योंकि हाइड एक्ट के प्रतिबंध भारत के संवर्द्धित और परिष्कृत उपकरणों के हस्तांतरण और भारी जल उपकरणों पर लागू होते हैं। ये प्रावधान बहुराष्ट्रीय अथवा अमेरिकी निगरानी प्रणाली के बावजूद लागू होते हैं।

यह भारत–अमेरिका के बीच हुए 123 एग्रीमेंट पर भी सवाल खड़े करता है जिसमें संवर्द्धित और परिष्कृत एवं भारी जल उपकरणों के हस्तांतरण को यह कहकर अलग रखा गया था कि ये दोनों देशों का विषय है, जिन पर इनके कानून के मुताबिक विनियामक और लाइसेंस नीतियां लागू होती हैं।

यहां तक कि भारत–फ्रांस और भारत–रूस के बीच हुए नागरिक परमाणु समझौते में भी संवर्द्धित और परिष्कृत एवं भारी जल उपकरणों के हस्तांतरण को सहयोग के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। एनएसजी द्वारा लगाया गया प्रतिबंध एक अन्य आधारभूत सच्चाई को भी सामने लाता है।

भारत हाइड एक्ट, 123 एग्रीमेंट और आइएईए के सुरक्षा समझौतों से बंधा हुआ है। सैन्य मामलों में परमाणु क्षमता से संपन्न होने के बावजूद भारत के साथ गैर परमाणु हथियार वाले राष्ट्र के तौर पर व्यवहार किया जाता है। इस कारण ऐसे राष्ट्रों पर परमाणु हथियारों के गैर–प्रसार वाली शर्तें लागू होती हैं, जबकि एनपीटी पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों पर अतिरिक्त दंड प्रावधान भी लागू होते हैं।

ताजा प्रतिबंध नई दिल्ली की उस पहेली का भी खुलासा करते हैं जिसके मुताबिक सरकार ने स्वच्छ और बिना शर्त एनएसजी से छूट मिलने की बात कही थी। मनमोहन सिंह ने देशवासियों को आश्वासन देकर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। इस संदर्भ में एक दूसरा तथ्य यह है कि एक अक्टूबर, 2008 को अमेरिकी कांग्रेस ने जिस समझौते की पुष्टि की वह प्रधानमंत्री द्वारा 17 अगस्त, 2006 को संसद में देश को दिए गए आश्वासन से अलग था। भारत–अमेरिका के बीच हुए परमाणु सहयोग स्वीकृति और अप्रसार वृद्धि अधिनियम (एनसीएएनईए)में साफ किया गया है कि 123 एग्रीमेंट हेनरी जे हाइड एक्ट का अतिक्रमण कर सकता है।

इसके अलावा इसमें कहा गया है कि अमेरिका द्वारा परमाणु ईंधन की आपूर्ति एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है न कि कानूनी और यह समझौता तब कुछ नहीं कर सकता यदि अमेरिका सहयोग बंद कर दे।

अंतिम समझौता अमेरिका को विशेष अधिकार देता है जिसमें भारत की केवल जरूरतों की ही चर्चा की गई है। यह कहना गलत न होगा कि समझौता मनमोहन सिंह सरकार के घोटालों, तोड़े गए वादों, गैर जनजवाबदेहिता, कुव्यवस्था और उसके छद्म आवरण की सच्चाई को ही बताता है। ❑

अमिताव घोष की पुस्तक : रिवर ऑफ स्मोक पर कुछ विचार

वैसे देखा जाए तो लेखक के मन में इतना ज्यादा अफीम का विषय नहीं था जब उसने इस उपन्यास को लिखना शुरू किया था। उसके मन में था कि औपनिवेशिक काल में बिहार से जो अनुबंधित मजदूरों का मामला था जिनको अंग्रेजो ने बिहार से ले जाकर दूसरे देशो में गुलाम बना कर काम लिया – इस विषय पर अन्वेषण करना। लेकिन ये खोज शुरू करते ही लगा के सब के सब रास्ते अंत में अफीम से होकर ही जाते हैं. कहानी एक चतुर पारसी व्यापारी बहराम के आसपास घूमती है. . .

■ कश्मीरी लाल

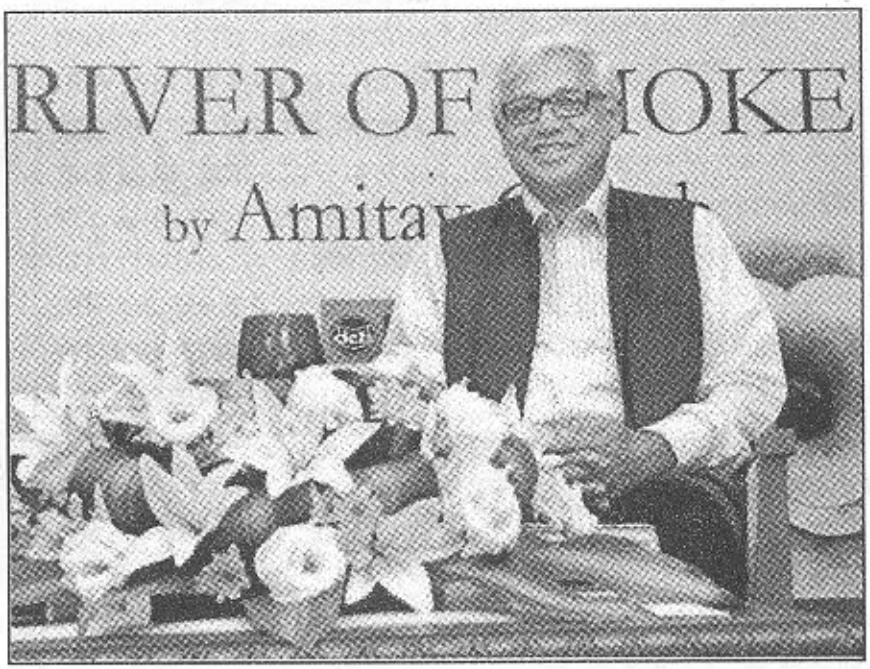

इस खूंखार साजिश को अंजाम देने के लिए अंग्रेजों ने धीरे धीरे चीन में प्रवेश करके वहां के लोगो को नशे की आदत डालनी शुरू की। कुछ समय जब इसके खतरनाक परिणाम आने शुरू हुए तो चीनी सम्राट इस चाल को समझ गया और उसने 1730 सन में अफीम का व्यापार ही पूरी तरह गैर कानूनी घोषित कर दिया।

रिवर ऑफ स्मोक : यह प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक अमिताव घोष की 500 पेज की बहुत चर्चित पुस्तक है और भारत में ही नहीं दुनिया में प्रसिद्ध हो रही है। इसमें एक सनसनीखेज कहानी है। चीन को दबाने के लिए 19वीं शताब्दी में योरोप ने एक चाल चली थी वहां के लोगों को अफीम की लत लगाने की। चीन के सम्राट ने विरोध किया तो अंग्रेजों और अमरीकी ताकतों ने वहां दो युद्ध किये जिसे अफीम के युद्ध कहा जाता है। 'जिस बेईमानी, चालाकी एवं शातिर तरीके से चीन को हराया गया वे आज भी गोरे मुल्कों का बाकी देशों को दबाने का तरीका है। आज के वैश्वीकरण, पेटेंट, विश्व बैंक, आदि के दाव–पेंच बहुत आसानी से इस युद्ध द्वारा समझे जा सकते है।

लेखक अंग्रेजी के सिद्ध–हस्त लेखक माने जाते है और इससे पहले की उनकी पुस्तक : सी ऑफ पॉपीज भी बुकर 2008 के लिए शोर्ट– लिस्ट हुई थी। कहने को इस विषय पर जो तीन पुस्तकें लिखने का निश्चय लेखक ने किया है, ये पुस्तक उसकी दूसरी किश्त है, लेकिन सभी पुस्तकों का अपना अलग अस्तित्व है।

मैंने इस पुस्तक के बारे में जो कुछ पढ़ा, सुना है या इस विषय के जानकारों से चर्चा हुई, इसके आधार पर इस 500 पृष्ठों को में पांच पैराग्राफ में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है यह प्रयास आपको पसंद आएगा।

पहला भाग : ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोप व अमरीकी ताकतों का चीन से जो दो युद्ध 1839 –42 एवं 1856 से 1860 के बीच हुए उनकी नीव में चाय की वो पत्ती थी जो चीन में पैदा होती थी और पूरे यूरोप में अत्यधिक लोकप्रिय हो गयी थी। गोरे मुल्कों के इसके बदले में बहुत अधिक मात्र में चांदी देनी पढ़ रही थी, जिससे बचने का वो कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक भयंकर साजिश रची। वो ये थी कि जैसे–तैसे चीन के लोगों को अफीम की लत लगवाई जाये और उससे जो कमाई हो उससे चाय का भुगतान किया जावे।

इस खूंखार साजिश को अंजाम देने के लिए अंग्रेजों ने धीरे धीरे चीन में प्रवेश करके वहां के लोगो को नशे की आदत डालनी शुरू की। कुछ समय जब इसके खतरनाक परिणाम आने शुरू हुए तो चीनी सम्राट इस चाल को समझ गया और उसने 1730 सन में अफीम का व्यापार ही पूरी तरह गैर कानूनी घोषित कर दिया। दूसरा शिकंजा उसने एक और कसा जिसके द्वारा कोई भी अंग्रेज चीन में प्रवेश ही नहीं कर सकता था और उनको 'कान्टन प्रणाली' कहा गया, क्योंकि चीन के मुख्य द्वार के पास कान्टन नामक द्वीप तक ही अंग्रेजो को आने जाने की अनुमति थी। लेकिन अंग्रेजों ने एक नयी रन–नीति चली और देखते ही देखते अंग्रेजों द्वारा भेजी गयी अफीम पूरे चीन में छा गयी। तो वो कैसे? आईये जरा उस शैतानी चाल को देखें इस दूसरे भाग में।

भाग दो : बिना चीनी सरकार की अनुमति के चीन में अफीम घर घर कैसे पहुँची, एक बेजोड़ अंग्रेजों का षड़यंत्र : अंग्रेजों का तरीका बहुत ही नायाब था। जिस पर्ल नदी के मुहाने पर ये द्वीप जिसका नाम लिनतिन था, उसके आसपास बहुत से द्वीप थे और चीन का उस पर कोई कब्जा नहीं था। इन पर चोर–डाकू रहते थे जैसे की आजकल भी दुनिया के कुछ भागों में हैं।

अंग्रेज बिहार में अफीम की खेती करवाते और गाजीपुर के कारखानों में उसे तैयार करवा कर मुंबई (तब बम्बई) लाते। वहां से विशाल जहाजों में पूरी सुरक्षा बंदोबस्त के साथ लिन टिन द्वीप या मकाऊ नामक स्थान तक ले जाते और वहां बिना मस्तूल के जहाजों में अफीम को रख देते। इसे पूरी तरह स्टोर करने के बाद वे चीनी अफसरों के आगे जाकर जहाज

क्या नायाब तरीके थे अंग्रेजो के कानून की धज्जियाँ उड़ाने के। इसी से तंग आकर चीन सम्राट ने जो दो युद्ध किये उसमें चीन की बुरी तरह हार हुई और जो असमान संधि अंग्रेजों से हुई, उसमें अफीम के व्यापार को कानून घोषित किया गया। दूसरी बात चीनी शासकों ने मानते हुए पर्ल नदी के मुहाने के इलाके को अंग्रेजो को देना तय हुआ। बस और क्या चाहते थे अंग्रेज! खुले आम अफीम बेच बेच कर चीन को तबाह किया और अपने देश में अकूत धन सम्पति ले गए।

को चेक करवाते – 'देखो हम कोई भी अफीम आदि नहीं लाये'। इधर यहाँ से छोटी तेज नौकाओं द्वारा ये अफीम चीन के दूरस्थ अड्डों और अमीरों की हवेलियों तक पहुँच जाती और कानून धरे के धरे रह जाते।

काले धंधे में वैसे तो सभी लोग शामिल थे, अंग्रेज, चीनी, अमरीकी, पारसी और भारतीय भी... लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे घिनोनी बात उसका ढोंग था। ब्रिटिश साम्राज्य इस सारे पाप को छुपाने के लिए हमेशा ही बहुत सुन्दर शब्दों का चयन करता था – 'हम ये सब आपकी भलाई के लिए कर रहे है, सद्भाव बढ़ाने और आप सबकी मुक्ति के लिए, जबकि असल में उनका मंतव्य था अति नीच श्रेणी का लालच, शो–बाजी और नस्लवाद।

क्या नायाब तरीके थे अंग्रेजो के कानून की धज्जियाँ उड़ाने के। इसी से तंग आकर चीन सम्राट ने जो दो युद्ध किये उसमें चीन की बुरी तरह हार हुई और जो असमान संधि अंग्रेजों से हुई, उसमें अफीम के व्यापार को कानून घोषित किया गया। दूसरी बात चीनी शासकों ने मानते हुए पर्ल नदी के मुहाने के इलाके को अंग्रेजो को देना तय हुआ। बस और क्या चाहते थे अंग्रेज! खुले आम अफीम बेच बेच कर चीन को तबाह किया और अपने देश में आकूत धन सम्पति ले गए।

लेकिन एक प्रश्न है कि क्या इस हेराफेरी के काम में कुछ नाम–चीन हस्तियाँ भी शामिल थी या आम व्यापारी ही लगा हुआ था? तो उत्तर सकारात्मक है और कौन कौन खास लोग थे इस पाप के धंधे में – जरा पढ़े तीसरे भाग में।

भाग तीन : इस पाप के धंधे में शामिल थे प्रमुख लोग : जब अमिताव से पूछा गया की क्या आम व्यापारी आदि ही इसमें शामिल थे तो उन्होंने कहा की उस समय की बहुत मशहूर हस्तियाँ भी इस धंधे में शामिल थे। अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दादा एंड्रूव डेलानो एक थे। 30वें राष्ट्रपति अमरीका के यानी केल्विन कोलिज के परिवार के लोग आदि आदि भी। उन्होंने एक और अहम खुलासा किया की ये पाप की कमाई लेकर लोग जब अपने देश में लोटते थे तो अपना नाम कमाने के लिए इस अफीम की कमाई से वहां की शिक्षण संस्थाओं का वित्त पोषण करते और इससे नेक नाम कमाते।

अमिताव का एक और कहना बहुत महत्त्व रखता है की इस काले धंधे में वैसे तो सभी लोग शामिल थे, अंग्रेज, चीनी, अमरीकी, पारसी और भारतीय भी... लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे घिनोनी

बात उसका ढोंग था।

ब्रिटिश साम्राज्य इस सारे पाप को छुपाने के लिए हमेशा ही बहुत सुन्दर शब्दों का चयन करता था – 'हम ये सब आपकी भलाई के लिए कर रहे है, सद्भाव बढ़ाने और आप सबकी मुक्ति के लिए, जबकि असल में उनका मंतव्य था अति नीच श्रेणी का लालच, शो–बाजी और नस्लवाद।

ये बुराइयाँ तो हर जगह व्याप्त रहती है लेकिन इसके लिए अच्छे–अच्छे शब्दों का चयन कोई ब्रिटिश साम्राज्यवाद से ही सीखें। लेकिन समझाने की बात है कि ऐसे सब तथ्यों को एक रोचक उपन्यास में कैसे ढाला है अमिताव ने। तो इसके लिए जरा चौथा भाग को देखें।

भाग चार : कथानक में कैसे पिरोया है ये एतिहासिक ताना–बाना: वैसे देखा जाए तो लेखक के मन में इतना ज्यादा अफीम का विषय नहीं था जब उसने इस उपन्यास को लिखना शुरू किया था। उसके मन में था कि औपनिवेशिक काल में बिहार से जो अनुबंधित मजदूरों का मामला था जिनको अंग्रेजो ने बिहार से ले जाकर दूसरे देशो में गुलाम बना कर काम लिया – इस विषय पर अन्वेषण करना। लेकिन ये खोज शुरू करते ही लगा के सब के सब रास्ते अंत में अफीम से होकर ही जाते हैं. कहानी एक चतुर पारसी व्यापारी बहराम के आसपास घूमती है जो इस जल्दी में है कि जैसे–तैसे अफीम पर प्रतिबन्ध लगने से पूर्व ही उसका जहाज मकाऊ पहुँच जाये और उसके लिए वो हर तरह का भ्रष्ट तरीका अपनाने को तैयार है। नशे और

वैसे देखा जाए तो लेखक के मन में इतना ज्यादा अफीम का विषय नहीं था जब उसने इस उपन्यास को लिखना शुरू किया था। उसके मन में था कि औपनिवेशिक काल में बिहार से जो अनुबंधित मजदूरों का मामला था जिनको अंग्रेजो ने बिहार से ले जाकर दूसरे देशो में गुलाम बना कर काम लिया – इस विषय पर अन्वेषण करना।

सेक्स की छोंक से कहानी उस वक्त का बहुत बारीकी से चित्रण करती है। एक अन्य पात्र पौलेट हे जो एक कोरीआयी मूल के वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता के साथ किसी मिथकीय स्वर्णिम कैमेलिया की खोज में चीन की यात्रा कर रहा हे। लोगों की टूटी–फूटी अंग्रेजी भाषा, वेश–भूषा और व्यवहार बहुत ही मनोरंजक ढंग से कथानक को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज

ये खोज शुरू करते ही लगा के सब के सब रास्ते अंत में अफीम से होकर ही जाते हैं. कहानी एक चतुर पारसी व्यापारी बहराम के आसपास घूमती है जो इस जल्दी में है कि जैसे–तैसे अफीम पर प्रतिबंध लगने से पूर्व ही उसका जहाज मकाऊ पहुँच जाये और उसके लिए वो हर तरह का भ्रष्ट तरीका अपनाने को तैयार है।

इस कथा का कोई सन्दर्भ हे क्या, कोई अर्थ हे क्या? इसे समझाने के लिए अब अंतिम भाग में प्रवेश करें...

भाग पांच: आज के सन्दर्भ में कहानी: बिलकुल सही – देखा जाये तो आज खुद चीन भी और अमरीका की ताकतें वही कर रही हे जो की उस समय की ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकतें कभी करती रही हैं। मोनसेंटो वही कंपनी हे जो कभी युद्ध में जहरीले अस्त्र–शस्त्र बनाती थी, युद्ध के बाद अब खेत के लिए उन्ही जहरीली चीजों का इस्तेमाल खेती में कीड़े–मार दवाइयों के नाम से कर रही हे. मकसद खेती का भला नहीं बल्कि अपना मोटा मुनाफा हे चाहे जमीन दुनिया की बंजर हो जाये। बीजों में बी टी तकनीक का प्रचालन भी दुनिया को लूटने की नयी साजिश हे. वाल–मार्ट जैसे मगरमच्छ आज भी खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश करके आम आदमी का रोजगार धंधा नष्ट करने पर तुले हुए हे। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ कोका कोला हो या पेप्सी के मार्केट पर कब्जा करने के षड्यंत्र देख लीजिये। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र पर कब्जे करने के लिए ऐसे तेल वाले देशो पर हमले – सबके सब अफीम युद्ध की याद दिलाते हैं. आज फिर जब भूमंडलीकरण के बीस साल हो गए हैं तो बहु–राष्ट्रीय कंपनियों का खुनी चेहरा पहचानने की जरूरत हे, और ये किताब या इस जैसा साहित्य एक नयी जाग्रति की लहर ला सकता हे. आप भी इस प्रकार के कुच्छ उदहारण दे सकते हे इस विषय लो समझाने के लिए, आपक इन्तजार रहेगा। ❑

हमारे लिए केवल एक ही चीज का मूल्य है। हम भगवान् के लिए अभीप्सा करते हैं, भगवान् के लिए जीते हैं, भगवान् के लिए कार्य करते हैं। – श्रीमाँ

बाबा रामदेव व समर्थकों पर पुलिस की बर्बरता

लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना सहन नहीं

अंग्रेजों के जमाने में अमृतसर में जलियांवालाबाग में जनरल डायर ने भी दिन में भीड़ को वहां से चले जाने के लिए 10–15 मिनट का समय दिया था परंतु देश में शासन कर रहे काले अंग्रेजों (जिन्हें हिन्दी बोलने में शर्म महसूस होती है) ने एक मिनट का भी समय रात एक बजे सोते हुए लोगों को नहीं दिया और न ही लोगों को वहां से जाने के लिए कहा गया। मंच पर से सभी को खदेड़ दिया गया पंडाल में हाहाकार मच गया। लोग घायल अवस्था में हताश व निराश होकर इधर उधर भागने लगे। ऐसी बर्बरता तो अंग्रेजों ने भी कभी नहीं की और बाद में अंग्रेजों ने जनरल डायर पर मुकदमा भी चलाया। क्या कांगेस की सरकार ऐसा करने पर पुलिस पर मुकदमा चलायेगी?

■ डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

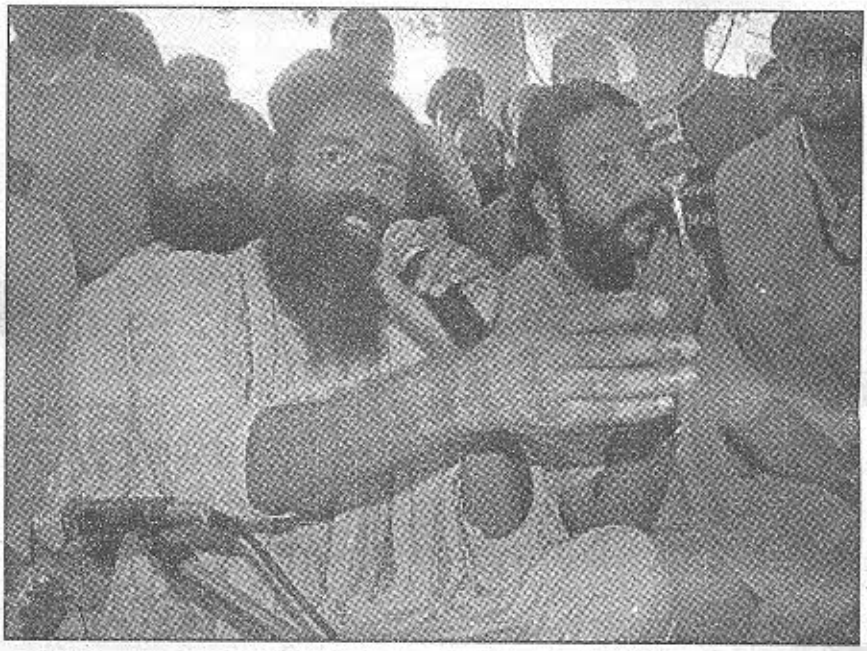

देश की आधे से अधिक आबादी गरीबी व बेरोजगारी से लड़ रही है। इसी के उन्मूलन के लिए बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अनशन की शुरुआत की थी लेकिन अनशन को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि बाबा रामदेव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ धमकी और उनके प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान को चारों ओर से घेर कर अभूतपूर्व हिंसा का तांडव शुरु कर दिया गया।

गत लगभग 15 वर्षों से योग गुरु के रुप में प्रसिद्ध बाबा रामदेव ने देश में काला धन, भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति, गरीबी, बिमारी को लेकर योग का प्रशिक्षण देते देते भारतवासियों को जागरुक करते हुए भारत स्वाभिमान आंदोलन चला रखा है जिसमें बाबा रामदेव का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश को जिन भ्रष्टाचारियों ने अनिवार्य रूप से गरीब बना कर लगभग 9,000 अरब डॉलर की रकम को देश से चुरा चुरा कर विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है वह धन येन केन प्रकेण देश में वापस आ जाये और देश में प्रत्येक गांव व नगर का निवासी एक अच्छे वातावरण में रह सके और गरीबी के कारण होने वाली बिमारियों से लोग ग्रस्त न हो सकें। इसके लिए बाबा रामदेव ने पतंजलि नाम से संस्था व ट्रस्ट भी बनाया।

बाबा रामदेव ने भगवा (साधु) वेश भी धारण किया परंतु भारत के छद्म धर्मनिरपेक्षतावादियों को उनका यह साधु वेश पसंद नहीं आ रहा था तथा देश के साथ धोखा करते हुए विदेशों में धन पहुंचाने वाले भ्रष्टाचारी नेताओं की आंख की किरकीरी ही बनते जा रहे थे। करोड़ों रुपयों की अकूत संपदा के स्वामी बनें हमारे राजनेता अपनी पोल खुलती देख कर बाबा रामदेव के विरोधी हो चले थे परंतु बाबा रामदेव ने अपने विरोध प्रदर्शन का लोकतांत्रिक तरीका ही बनाये रखा। योग गुरु होने के नाते बाबा का मानना है कि योग अर्थात जोड़। मनुष्य का सत्य से योग, श्रेष्ठ योग है। शरीर का स्वास्थ्य से योग, श्रेष्ठ योग है। इस योग के लिए महर्षि पतंजलि ने हजारों वर्ष पूर्व योगासन की एक लम्बी सूची समाज को दे दी थी। बाबा रामदेव सैटेलाइट टीवी के माध्यम से आसनों को प्रदर्शन करके योगासन का प्रचार व प्रसार कर रहे थे। जिसको देख व सुन कर विश्व के प्रत्येक वर्ग के लोग घर बैठे बैठे योग करके स्वस्थ्य रहने लगे थे। बाबा रामदेव के समर्थकों की संख्या

करोड़ों में पहुंच गई थी।

बाबा रामदेव ने 4 जून 2011 दिन शनिवार से दिल्ली के प्रसिद्ध रामलीला मैदान में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में तथा विदेशों में जमा काला धन को भारत में वापस लाने की मांग को लेकर सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा कर दी। योग और सत्याग्रह का योग हानिकारक नहीं है। लेकिन योग व सत्याग्रह में राजनीति का योग नहीं होना चाहिए यही असामाजिक हो जाता है। यदि योग में राजनीति आ गई तो भी असामाजिक हो जाता है यदि सत्याग्रह में राजनीति आ गई तो भी असामाजिक होगा। बाबा रामदेव व उनके समर्थक योग और सत्याग्रह में राजनीति नहीं लाने का प्रयास कर रहे थे। परंतु राजनीति बाज राजनेता बाबा रामदेव व उनके आंदोलन को अपने बचाव के लिए सदैव राजनीति के चश्में से ही देखता जिसमें जनता में राजनेता की पूर्व स्थापित छवि उज्जवल की उज्जवल बनी रहे।

बड़बोले कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह बाबा रामदेव को संत कम व्यवसायी ज्यादा मानते रहे। बाबा रामदेव को कुछ ईष्यालु साधु संत बाबा रामदेव का विरोध करते हुए बाबा रामदेव को साधु नहीं मानते थे। वे बाबा रामदेव को व्यापारी व उद्योगपति मानते हुए यह कहते रहे कि बाबा रामदेव को साधु वस्त्र त्याग कर पेंट व शर्ट, कुर्ता, पायजमा अथवा सफारी सूट पहनना चाहिए। बाबा रामदेव को साधु के रूप में रहकर उद्योगपति और व्यवासायी बने रहना उनका संताचरण नहीं हो सकता। केन्द्र सरकार के चार–चार वरिष्ठ मंत्री बाबा रामदेव की अगवानी करने के लिए दिल्ली के हवाई अड्डे पर 1 जून 2011 गए तथा योग और सत्याग्रह से राजनीति का योग हो गया। लगभग ढाई घंटे तक चली वार्ता विफल रही परंतु बातचीत का राजनीतिक रास्ता खुल गया तथा राजनीति बाज राजनेता किसी बाज की तरह से बाबा रामदेव का 4 जून को शुरु होने वाले अनशन को किसी भी प्रकार से विफल करने पर उतारू थे। बातचीत की ढोंग व छल प्रपंच की राजनीति की गई। बाबा रामदेव का अनशन किसी न किसी प्रकार धूल धूसरित करना सरकार व उसके मंत्रियों का मुख्य उद्देश्य हो गया था। बाबा रामदेव स्वयं को राजनीति से दूर रख कर वरिष्ठ मंत्रियों के स्वभाव, बातचीत, हावभाव पर यकीन करते रहे। बाबा रामदेव व उनके अनुयाईयों का हौंसला बढ़ गया और उनमें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तथा मंत्रियों की राजनीतिक चाल को बाबा रामदेव समझ न सके। वे दिल्ली के एक पंचतारा होटल में बाबा रामदेव व उनके महामंत्री बालकृष्ण को बुला कर एक तरफ सरकार के विभिन्न विभागों से आये अधिकारीं विदेश में जमीन खरीदने को लेकर धमका भी रहे थे और समझौते की भी बात कर रहे थे। मंत्रियों की सारी कवायद बता रही थी कि राजनीति, योग व सत्याग्रह को स्वयं के लपेटे में ले रही थी।

एक कांग्रेसी नेता ने कहा भी कि सरकार को कम से कम यह सफलता तो मिली कि बाबा रामदेव का अभियान भाजपा–शिवसेना और सिविल सोसायटी (अन्ना हजारे) से अलग कर दिया गया। यह बयान ही कांग्रेस के छल प्रपंच की राजनीति को दर्शाता है। भ्रष्टाचार के विरोध में सब खडे है परंतु दिखावे के लिए वे लोग भी खड़े है जो भ्रष्टाचार में आंकठ डूबे है।

बाबा रामदेव की कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो कि देशहित में नहीं हो। बाबा रामदेव की मांग जन लोकपाल की नियुक्ति है इस मांग को लेकर अन्ना हजारे सामने आये और अन्ना कह रहे है कि सरकार ने उनको धोखा दिया है और अन्ना हजारे की सलाह बाबा रामदेव को यह थी कि वे सरकार से बच कर रहें। बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री के पद के लिए सीधे जनता से मतदान की मांग की। बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचारियों की मृत्युदंड की मांग की है। बाबा रामदेव ने मांग की कि बड़े नोट (500, 1000 रुपये के) चलन से बाहर कर दिये जायें बाबा रामदेव की मांग है कि भारतीयों के द्वारा विदेशों में जमा काला धन राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित की जानी चाहिए।

कांग्रेस की केन्द्रीय सरकार इन्हीं सब मांगों को माने जाने का दिखावा करती रही और रामलीला मैदान में 4–5 जून 2011 की रात एक बजे पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स के लगभग 10,000 जवान सोते हुए बाबा रामदेव व उनके समर्थकों पर आंसू गैस के गोले छोड़ कर व बाबा रामदेव को मंच से दो युवको ने नीचे से पैर में छटका देकर नीचे गिरा दिया और कई घंटे बाद बाबा रामदेव किसी प्रकार वहां से हरिद्वार पहुंच गये। रामलीला मैदान में एक लाख स्त्री, बच्चों व बुजुर्गों पर पुलिस की लाठियां व आंसू गैस के गोले बडी मात्रा में छोड़े जा रहे थे। अंग्रेजों के जमाने में अमृतसर में जलियांवालाबाग में जनरल डायर ने भी दिन में भीड़ को वहां से चले जाने के लिए 10–15 मिनट का समय दिया था परंतु देश में शासन कर रहे काले अंग्रेजों (जिन्हें हिन्दी बोलने में शर्म महसूस होती है) ने एक मिनट का भी समय रात एक बजे सोते हुए लोगों को नहीं दिया और न ही लोगों को वहां से जाने के लिए कहा गया। मंच पर से सभी को खदेड़ दिया गया पंडाल में हाहाकार मच गया। लोग घायल अवस्था में हताश व निराश होकर इधर उधर भागने लगे।

ऐसी बर्बरता तो अंग्रेजों ने भी कभी नहीं की और बाद में अंग्रेजों ने जनरल डायर पर मुकदमा भी चलाया। क्या कांगेस की सरकार ऐसा करने पर पुलिस पर मुकदमा चलायेगी? रामलीला मैदान में किसी भी औरत व बच्चे व बुजुर्ग के पास लाठी व डंडे तक नहीं थे। शांति से प्रदर्शन किया जा रहा था। साफ सुथरे मैदान में पत्थर नहीं थे तो फिर पुलिस पर पथराव

कहां से हुई? पुलिस ने सोते हुए सत्याग्रहियों पर प्रहार किया। मां बहन व बच्चों को भी नहीं छोड गया। सत्याग्रहियों के चेहरे पर डर, उदासी, आक्रोश के तीनों भाव एक एक कर झलकते रहे। किसी की दोनों टांगे टूटी तो किसी की रीढ़ की हड्डी। सत्याग्रही दिल्ली पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स के जवानो की बर्बरता के शिकार हो गये।

बाबा रामदेव व सत्याग्रहियों को रामलीला मैदान से जबरदस्ती हटाये जाने की घटना को न्यूयार्क की एक भारत अमरीकी संस्था ने इसे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर खतरनाक हमला करार दिया। न्यूयार्क की अमेरिकन इंटलेक्चुअल फोरम (आई ए आई एफ) ने एक वक्तव्य में कहा कि इस शांतिपूर्ण आंदोलन के पीछे बाबा रामदेव का उद्देश्य गरीब भारतीयों से चुरा–चुरा कर विदेशों में जमा काले धन लगभग 9,000 अरब डॉलर की राशि को भारत में वापस लाना था। फोरम के अध्यक्ष नारायण कटारिया का कहना था कि किसी भी सूरत में इस प्रदर्शन से देश की कानून व्यवस्था को कोई हानि नहीं पहुंचती जैसा कि केन्द्र सरकार दावा कर रही है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लगभग 1,00000 बच्चें, महिलाओं, और बूढ़ों सहित बेकसूर लोगों पर पुलिस पर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़ना व बल प्रयोग को लोकतंत्र में कोई कैसे जायज ठहरा सकता है। यह तो पश्चिम एशिया के देशों में तानाशाहों के द्वारा चलाये जाने वाले नंगे फासीवाद की तरह की घटना है।

रामलीला मैदान में रात 12 बजे तक सब कुछ सामान्य था। 12 बजे के बाद पुलिस ने रामलीला मैदान की घेराबंदी करनी शुरु कर दी एक बजे तक लगभग 10 हजार पुलिस के जवान मैदान में चारों तरफ एकत्र हो गये और सत्याग्रहियों को वहां से जबरदस्ती खदेड़ना शुरु कर दिया परन्तु सत्याग्रहियों की संख्या ज्यादा होने के कारण उन्हें खदेड़ पाना पुलिस के लिए मुश्किल था। रात एक बजे और पुलिस बल की कंपनियों को बुलाया गया तथा कुछ सादे कपड़ों में व कुछ वर्दीधारी पुलिसकर्मी मंच तक पंहुच गये और सत्याग्रहियों के साथ बदतमीजी करनी शुरु कर दी और आधी रात के बाद दहशत का जो आलम बनाया गया वह सत्याग्रहियों को आजीवन याद रहेगा। पुलिस ने पंडाल को घेर कर चारों तरफ से सत्याग्रहियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरु कर दिये लोग वहां से जैसे तैसे गिरते पड़ते भाग रहे थे।

बाबा रामदेव व सत्याग्रहियों को रामलीला मैदान से जबरदस्ती हटाये जाने की घटना को न्यूयार्क की एक भारत अमरीकी संस्था ने इसे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर खतरनाक हमला करार दिया। न्यूयार्क की अमेरिकन इंटलेक्चुअल फोरम (आई ए आई एफ) ने एक वक्तव्य में कहा कि इस शांतिपूर्ण आंदोलन के पीछे बाबा रामदेव का उद्देश्य गरीब भारतीयों से चुरा–चुरा कर विदेशों में जमा काले धन लगभग 9,000 अरब डॉलर की राशि को भारत में वापस लाना था।

भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि रामलीला मैदान में पुलिस की कार्यवाही से आपातकाल की याद ताजा हो गई है। प्रसिद्ध समाज सेवक अन्ना हजारे ने कहा कि बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर कार्यवाही देश की लोकशाही पर कलंक की तरह है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि देश में अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वालों पर क्या डंडा चलेगा? उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री कु. मायावती ने कहा कि रामलीला मैदान में जो कुछ भी हुआ वह आलोकतांत्रिक है। पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी होनी चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बाबा रामदेव के साथ रामलीला मैदान पर सरकार ने जो कुछ किया वह रावणलीला है। बाबा रामदेव ने कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। कांग्रेस सरकार उनका एनकांउटर करना चाहती थी। उनके साथ पशुतापूर्ण व्यवहार किया गया। उनकी आंखों के सामने राष्ट्रभक्तों को घसीट–घसीट कर मारा गया। वे स्वंय महिला के वस्त्र पहन कर महिलाओं के बीच छिप गये यदि वे ऐसा नहीं करते तो या तो उन्हें मार दिया जाता या फिर गायब कर दिया जाता यदि उनके जीवन पर भविष्य में कोई खतरा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी संप्रग की प्रमुख सोनिया गांधी और कांग्रेस की होगी। बाबा रामदेव ने केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल को कुटिल करार दिया। बाबा रामदेव ने कहा कि सोनिया के दिल में भारत की महिलाओं व बच्चों के लिए कोई संवेदना नहीं है। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि पुलिस की कार्यवाही ठीक व जायज थी। बाबा रामदेव ठग है और उनके साथ वही हुआ जो एक ठग के साथ होना चाहिए था। सिंह ने 1994 से लेकर अब तक की बाबा रामदेव की गतिविधियों की जांच की मांग की। संतोष हेगड़े ने कहा कि बाबा रामदेव यदि ठग है तो सरकार के चार वरिष्ठ मंत्री हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी करने क्यों गये? सरकार इतने दिन से उनसे बात क्यों कर रही थी? बाबा रामदेव व मंत्रियों के बीच विफल हुई बातचीत को बाबा रामदेव ने विश्वासघात बताया। आचार्य बालकृष्ण से पत्र लिखवाने को केन्द्र के मंत्रियों ने होटल के बंद कमरे में दबाव दिया और

कहा गया कि अन्ना हजारे आपके मंच पर आते है तो ठीक नहीं होगा। पांच घंटे तक होटल में हुई बातचीत के समय वहां मौजूद सरकारी अधिकारी बालकृष्ण से निरंतर पूछताछ कर दबाब बनाते रहे और प्रधानमंत्री को मात्र दिखाने के लिए उनसे जबरन एक पत्र लिखवाया गया जिसको कपिल सिब्बल ने 4 जून की सायं को प्रेस वार्ता करके पत्रकारों के समक्ष प्रदर्शित कर दिया और बाबा रामदेव को झूठा ठहरा कर बाबा रामदेव के आंदोलन की हवा निकालने की जुगत की गई।

बाबा रामदेव के 4 जून 2011 से शुरु हुआ आंदोलन के पर्दे के पीछे के.एन गोविंदाचार्य, अजित डोभाल, एस गुरुमूर्ति, महेश जेठमलानी तथा वेद प्रताप वैदिक इत्यादि की अहम भूमिका बतायी जा रही है। यही पांचों लोग बाबा रामदेव की उस कोर टीम का हिस्सा है जिनसे राय विचार कर बाबा रामदेव लगातार केन्द्र सरकार को चुनौती दे रहे है।

अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के मुददे पर दूध के जले है वह बाबा रामदेव को छाछ भी ठंडा कर पीने की नसीहत दे रहे थे। सरकार वादा करके पीछे हट जाती है। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिगुल बजा कर सरकार के चैन को छीन लिया था और फिर बाबा रामदेव ने सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया था। अन्ना हजारे ने बाबा रामदेव को पहले ही केन्द्र सरकार से सावधान कर दिया था।

यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबा रामदेव व उनके समर्थकों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही को देश का उच्चतम न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग प्रथम दृष्टया अनुचित व अनावश्यक मान रहे है परन्तु देश के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने इस कार्यवाही को जायज व सही ठहराया है। यह कार्यवाही जितनी बर्बरतापूर्ण थी उतनी ही मूर्खतापूर्ण भी क्योंकि बाबा रामदेव व उनके समर्थकों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के तौर तरीके किसी भी क्षण एक बड़ी त्रासदी में बदल सकते थे। यह अत्यन्त खेदजनक व चिन्ता जनक है कि जिस पुलिस कार्यवाही की देश भर में चौतरफा निन्दा हो रही हों उसको प्रधानमंत्री व गृहमंत्री सही ठहरा रहे हों। संवेदनशील समझे जाने वाले राजनेता की छवि रखने वाले प्रधानमंत्री से ऐसे विचित्र बयान की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं थी। उनके इस आकलन से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि रात के अंधेरे में सोते लोगों पर पुलिस धावा बोलने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं रह गया था। बिडम्बना है कि प्रधानमंत्री अपने इस आकलन को ईमानदार बता रहे है।

क्या मनमोहन सिंह यह बताएंगे कि ऐसा एकदम से क्या हो गया था कि सोते हुए निहत्थे लोगों पर पुलिस की बर्बरता लाजिमी हो गई थी। क्या बाबा रामदेव व उनके समर्थक रामलीला मैदान में आकर भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन करना कोई गुनाह था। रामलीला मैदान को मध्य रात्रि में ही एकदम से खाली कराने की कार्यवाही थोड़ी सी भी तमीज व शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं की गई? यदि बाबा रामदेव व उनके समर्थक अराजक व अंवाछित थे तो उन्हें दिल्ली आने की क्यों दिया गया? चार वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री बाबा रामदेव से दो तीन दिन तक क्या क्या बात करते रहे? यदि प्रधानमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे है तो पहले अन्ना हजारे और बाद में बाबा रामदेव को दिल्ली क्यों आना पडा? स्पैक्ट्रम घोटाले की जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में क्यों लेना पडा? क्या केन्द्र सरकार ने कभी किसी घोटाले को उजागर किया है? सभी घोटाले मीडिया, या आरटीआई की अर्जी या सीएजी की रिपोर्ट की सक्रियता के कारण ही उजागर हो सके है।

भारत में यह कैसा लोकतंत्र हो गया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने देश के हित के लिए भी नहीं लड़ सकता। नेताओं को देश के लिए लडना अच्छा नहीं लगता और अब तो लोगों को अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है। पहले तो कोई व्यक्ति देश के लिए लड़ना ही नहीं चाहता और यदि कोई देश के लिए लड़ता है तो उस पर पुलिस का चाबुक चल जाता है। देश की आधे से अधिक आबादी गरीबी व बेरोजगारी से लड़ रही है। इसी के उन्मूलन के लिए बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अनशन की शुरुआत की थी लेकिन अनशन को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि बाबा रामदेव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ धमकी और उनके प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान को चारों ओर से घेर कर अभूतपूर्व हिंसा का तांडव शुरु कर दिया गया। आंसू गैस के गोले छोड़ कर पंडाल में आग लगा दी गई महिलाओं व बच्चों को बुजुर्ग सहित लाठी से मारापीटा गया क्या है यही है भारत का लोकतंत्र जिस पर हम अभिमान करते है।

बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को सादर मंच पर बुला कर अपने कुकृत्य के लिए सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को बाबा रामदेव व अन्ना हजारे से क्षमा याचना करनी चाहिए यदि कांग्रेस ऐसा करने के लिए तत्पर नहीं है तो मनमोहन सिंह की सरकार को देश के हाथों अपनी दुर्गति के लिए तैयार रहना चाहिए। देश की जनता को चाहिए कि किसी भी कांग्रेसी को अपने आसपास न आने दें। मीडिया भी मनमोहन सिंह से मात्र एक प्रश्न ही पूछे कि अनशन स्थल पर बैठी महिलाओं और बच्चों का क्या जुर्म था जो उन पर रामलीला मैदान में लाठी बरसाई गई। राहुल गांधी ने देश में हुई इस महत्वपूर्ण घटना पर कुछ नहीं कहा। हो सकता है कि वे इस घटना की गौरव गाथा तैयार कर रहे हों क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार ने एक लोकतांत्रिक आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया है। हो सकता है कि कांग्रेस का यह कृत्य उसके ताबूत में आखिर कील साबित हो। ❑

समस्या

पूर्वोत्तर में गहराता खतरा

पूर्वोत्तर के आतंकी संगठनों के साथ माओवादियों का मिलना सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर खतरा है। परोक्ष रूप से चीन भारत को अस्थिर करने में जुटा है। भारत को हजार घाव दे कर उसे टुकड़ों में बांटना पाकिस्तान का घोषित एजेंडा है, किंतु इस घोषित एजेंडे को अमलीजामा पहनाना चीन की अघोषित नीति है। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में जिहादियों को प्रशिक्षण व ठिकाना उपलब्ध कराने के पीछे चीन का बड़ा हाथ है।

■ बलवीर पुंज

हाल ही में पूर्वोत्तर प्रांतों में सक्रिय पांच आतंकी समूहों के एकीकरण की प्रक्रिया म्यांमार की धरती पर चीनी खुफिया विभाग के सौजन्य से संपन्न हुई। इस घटना ने एक बार फिर भारत को अस्थिर और खंडित करने के चीनी एजेंडे को रेखांकित किया है।

दूसरी ओर जिस तरह भारतीय सत्ता अधिष्ठान चीन के साम्राज्यवादी व भारत विरोधी एजेंडे की अनदेखी करता आया है उससे सन बासठ के अपमानजनक अनुभव की पुनरावृत्ति का खतरा और बढ़ जाता है। पूर्वोत्तर प्रांतों में सक्रिय पांच आतंकी समूहों के एकीकरण में स्वतंत्र पूर्वोत्तर देश के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (एनएससीएन) के नेता एसएस खापलांग के नेतृत्व में उल्फा, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ कांगलेपाक आदि आतंकी संगठनों के नेताओं की इस बैठक में सीपीआई (माओवादी) के नेताओं के शामिल होने की भी खबर खुफिया एजेंसियों को है।

स्वतंत्र संप्रभु पूर्वोत्तर देश के गठन की प्रेरणा के पीछे चीनी खुफिया अधिकारियों का हाथ है। पूर्वोत्तर के आतंकी संगठनों के साथ माओवादियों का मिलना सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर खतरा है। परोक्ष रूप से चीन भारत को अस्थिर करने में जुटा है। भारत को हजार घाव देकर उसे टुकड़ों में बांटना पाकिस्तान का घोषित एजेंडा है, किंतु इस घोषित एजेंडे को अमलीजामा पहनाना चीन की अघोषित नीति है। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में जिहादियों को प्रशिक्षण व ठिकाना उपलब्ध कराने के पीछे चीन का बड़ा हाथ है।

भारत में सक्रिय उल्फा, नक्सली और माओवादियों के साथ इस्लामी अलगाववादियों को प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में पाकिस्तान के साथ चीन का भी योगदान है। भारत की दो हजार मील अंतरराष्ट्रीय सीमा चीन के साथ लगती है। आजादी से लेकर अब तक इस सीमा पर विवाद बरकरार है। चीन ने अक्साई चिन के 38 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जहां अवैध कब्जा कर रखा है, वहीं वह अरुणाचल प्रदेश को भारत का अंग नहीं मानता। चीन तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की धारा को भी मोड़ने का प्रयास कर रहा है।

भारत में सक्रिय उल्फा, नक्सली

और माओवादियों के साथ इस्लामी अलगाववादियों को प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में पाकिस्तान के साथ चीन का भी योगदान है। भारत की दो हजार मील अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ लगती है। आजादी से लेकर अब तक इस सीमा पर विवाद बरकरार है। चीन ने अक्साई चिन के 38 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जहां अवैध कब्जा कर रखा है, वहीं वह अरुणाचल प्रदेश को भारत का अंग नहीं मानता। चीन तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की धारा को भी मोड़ने का प्रयास कर रहा है। साथ ही तिब्बत में चीन आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास कर रहा है।

चीन दशकों से इस दिशा में प्रयासरत है, किंतु सन 2008 में उसने पहली बार दुनिया को बताया कि वह जांगमू में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने वाला है। यह क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र होने की दृष्टि से संवेदनशील है, किंतु सामरिक हित होने के कारण इन खतरों की अनदेखी कर वहां 510 मेगावाट वाले पनबिजली प्रोजेक्ट पर काम जारी है। इसके अतिरिक्त तिब्बत और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की घेराबंदी के लिए कई अन्य प्रोजेक्ट पर चीन तेजी से काम कर रहा है। सेटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि मध्य चीन के देलिंगा और दा कैदाम में कम से कम साठ ऐसे लांचिंग पैड विकसित किए गए हैं, जहां से उत्तरी भारत को निशाना बनाकर परमाणु मिसाइल दागी जा सकती हैं।

चीन द्वारा विकसित डीएफ–31 मिसाइल की मारक क्षमता 11,200 किलोमीटर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बंदरगाहों में चीन ने अपने नौसैन्य अड्डे स्थापित कर रखे हैं। पाकिस्तान के ग्वादर में तैनात चीनी मिसाइलों की मारक क्षमता इतनी है कि मुंबई जैसे शहर उसकी जद में हैं। चीन न केवल सामरिक दृष्टि से भारत की घेराबंदी कर रहा है, बल्कि वह भारत के राजनीतिक प्रभुत्व को भी कुंद करने का प्रयास कर रहा है।

श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान को भारी–भरकम वित्तीय सहायता देकर चीन उन्हें अपने पाले में करने की जुगत में है। यह अतिशयोक्ति नहीं कि चीन की हर चाल में आने वाले दो–तीन दशकों की रणनीति भरी होती है। नेपाल में चीन ने माओवादियों के सहयोग से एक ऐसा वर्ग पोषित किया है, जो घोर भारत विरोधी और चीनपरस्त है। भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए चीनी तकनीक से बने जाली नोटों की खेप पाकिस्तान से निरंतर आ रही है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के औषध कारोबार को क्षति पहुंचाने के लिए चीन में नकली दवाइयां बनाई जा रही हैं और उन पर 'मेड इन इंडिया' का लेबल लगाकर दूसरे देशों में बेचा जा रहा है। जम्मू–कश्मीर सरकार ने पिछले साल केंद्र को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन इंच–इंच कर भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है। सीमा पर बड़े पैमाने पर बंकर आदि का निर्माण कार्य चल रहा है। लद्दाख और उत्तराखंड में भारतीय थल और नभ सीमा का बारंबार अतिक्रमण वस्तुतः 1962 में भारत की पीठ में छुरा घोंपने वाले चीन की विस्तारवादी मंशा को ही रेखांकित करता है।

चीनी सैनिकों द्वारा किए जाने वाले भारतीय सीमा के अतिक्रमण को वर्तमान सत्ता अधिष्ठान सामान्य घटना बताता है, जबकि तिब्बत और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में युद्धस्तर पर आधारभूत संरचनाओं का विकास कर चीन हमारी देहरी तक चढ़ आया है। पूर्वोत्तर के आतंकी संगठनों के साथ माओवादियों की साठगांठ नई बात नहीं है।

दिसंबर, 2010 में पश्चिम बंगाल सीपीआई(माओ) के राज्य सचिव सुदीप चोंगदार की गिरफ्तारी के बाद ही इसका खुलासा हुआ था कि पीएलए के माध्यम से माओवादियों को भारी मात्रा में गोलाबारूद और हथियार मिल रहे हैं। इस खुलासे के बावजूद केंद्र सरकार इन अलगाववादी संगठनों पर लगाम कसने के बजाय उनसे मैत्री वार्ता करने को लालायित रही है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि अलग–अलग कारणों से भारत को अस्थिर व खंडित करने में लगे संगठन – वे चाहे इस्लामी संगठन हों या विदेशी वित्त से पोषित चर्च का एक भाग या स्थानीय कारणों से उल्फा जैसे पूर्वोत्तर के आतंकी संगठन उन सबको एक कड़ी में जोड़ने, उनके बीच बेहतर समन्वय कायम करने और उन्हें सैन्य व वैचारिक अस्त्र उपलब्ध कराने के पीछे चीन का हाथ है।

भारत को भीतर से कमजोर व अस्थिर करना चीन का एजेंडा है। म्यांमार का यह दावा कि वह अपनी जमीन का दुरुपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा, झूठा साबित हुआ है। पश्चिमी देश लोकतंत्र के दमन के लिए जहां म्यांमार के घोर आलोचक हैं, वहीं चीन हर कदम पर उसके साथ खड़ा है। म्यांमार में पूर्वोत्तर के अलगाववादी संगठनों का मिलनोत्सव वस्तुतः चीनी रणनीति का हिस्सा है। सत्ता अधिष्ठान को इसे चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। पड़ोसी देशों के साथ मैत्री कायम करने की छटपटाहट में इतिहास के सबक को भूलना नहीं चाहिए। ❑

जीवन धारा बचाने का अभियान

करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र मानी जाने वाली गंगा का शोषण बहुआयामी है क्योंकि स्वयं उसके अधिकतर श्रद्धालु भक्त भी गंगा–भक्ति को सामान्य अनुष्ठान से अधिक कुछ नहीं मानते। अगर मानते होते तो किसी भी सरकार में यह दमखम नहीं होता कि वह करोड़ों नागरिकों की इच्छा के विरुद्ध गंगा के अस्तिव के साथ गंभीर छेड़छाड़ करने का साहस कर सके। इसकी त्रासदी का एक बड़ा आयाम हैं वे पनबिजली परियोजनाएं, जिनके कारण न केवल इसकी धारा मोड़ने के लिए इसे जगह–जगह बांधा जा रहा है अपितु हजारों किलोमीटर तटीय क्षेत्रों के जलमग्न होने का खतरा भी पैदा किया जा रहा है।

■ जवाहरलाल कौल

जरूरी नहीं कि गंगा संरक्षण के नाम पर उत्तराखंड सरकार बड़ी पनबिजली योजनाओं के बारे में उमा भारती से सहमत हो। मनमोहन सरकार में भी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के पक्षधरों की कमी नहीं है। बहरहाल, उमा कहती हैं कि गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित हो और सोनिया ने माना कि इस पर विचार होना चाहिए। फिलहाल यह धारा के विरुद्ध चलने का काम है लेकिन धारा के विपरीत चलने से ही गंगा की धारा बचाई जा सकती है।

इस वर्ष कुंभ के दौरान गंगा को बचाने के लिए आरंभ किए गए आंदोलन के बाद से गंगा कुछ और मैली हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अधिकतर क्रशरों को बंद करने के बावजूद गंगा को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में संकल्पहीनता साफ दिखाई देती है। स्वामी निगमानंद की मौत केवल एक क्रशर के न हटने के कारण हुई, जिसे हटाने का आश्वासन प्रशासन ने तब दिया जब निगमानंद कोई भी प्रतिक्रिया देने योग्य नहीं रह गए थे। उनकी हत्या क्रशर माफिया ने कराई या वे अनशन के कारण मरे, यह तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा लेकिन यह गंगा की त्रासदी का एक ही आयाम है।

करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र मानी जाने वाली गंगा का शोषण बहुआयामी है क्योंकि स्वयं उसके अधिकतर श्रद्धालु भक्त भी गंगा–भक्ति को सामान्य अनुष्ठान से अधिक कुछ नहीं मानते। अगर मानते होते तो किसी भी सरकार में यह दमखम नहीं होता कि वह करोड़ों नागरिकों की इच्छा के विरुद्ध गंगा के अस्तिव के साथ गंभीर छेड़छाड़ करने का साहस कर सके। इसकी त्रासदी का एक बड़ा आयाम हैं वे पनबिजली परियोजनाएं, जिनके कारण न केवल इसकी धारा मोड़ने के लिए इसे जगह जगह बांधा जा रहा है अपितु हजारों

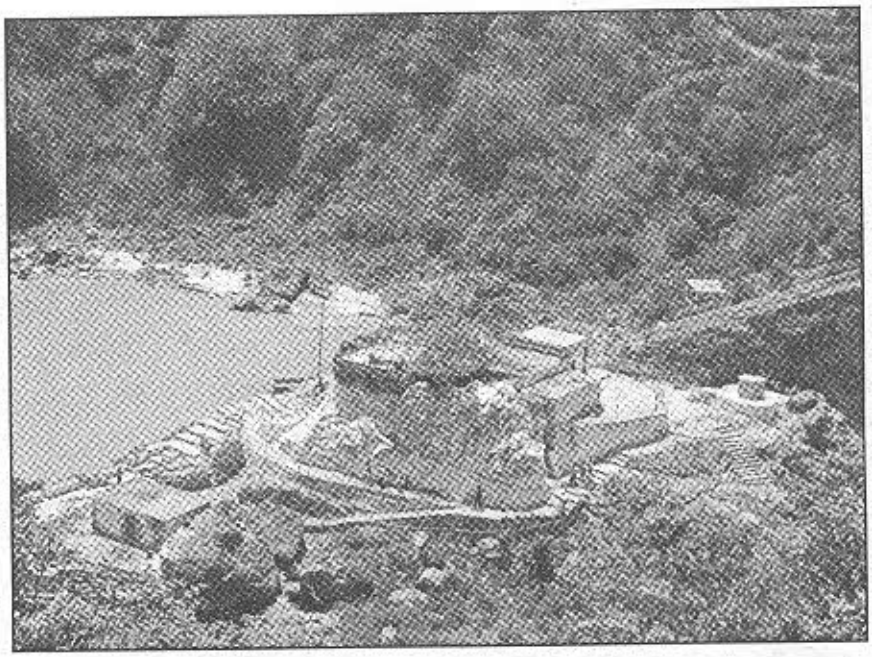

आजकल श्रीनगर के पास निर्माणाधीन पनबिजली परियोजना चर्चा में हैं। इस परियोजना का विस्तार करने के लिए बांध की ऊंचाई 350 फीट तक बढ़ाने की योजना है। इससे न केवल आसपास का रिहायशी इलाका डूब जाएगा अपितु एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर को भी जल समाधि लेनी पड़ सकती है। धारी देवी के नाम से प्रसिद्ध उक्त ऐतिहासिक मंदिर को अलकनंदा का पानी ही अपने में समा देगा देगा जिसके कारण क्षेत्र में यह नदी गंगा भक्तों की पूजा अर्चना का केंद्र रही है।

किलोमीटर तटीय क्षेत्रों के जलमग्न होने का खतरा भी पैदा किया जा रहा है।

आजकल श्रीनगर के पास निर्माणाधीन पनबिजली परियोजना चर्चा में हैं। इस परियोजना का विस्तार करने के लिए बांध की ऊंचाई 350 फीट तक बढ़ाने की योजना है। इससे न केवल आसपास का रिहायशी इलाका डूब जाएगा अपितु एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर को भी जल समाधि लेनी पड़ सकती है। धारी देवी के नाम से प्रसिद्ध उक्त ऐतिहासिक मंदिर को अलकनंदा का पानी ही अपने में समा देगा देगा जिसके कारण क्षेत्र में यह नदी गंगा भक्तों की पूजा अर्चना का केंद्र रही है।

उमा भारती लंबे समय से गंगा को बचाने के अभियान में जुटी हैं। फिर से राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होने से पहले ही उन्होंने पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि बांध के कारण डूबा क्षेत्र में आने वाले धारी देवी मंदिर को डूबने से बचाया जाए। इसकी प्रतिक्रिया में जयराम रमेश ने अलकनंदा परियोजना पर काम रूकवा कर एक समिति का गठन किया।

जैसा कि ऐसी समितियों में होता रहा है, सरकारी और गैर–सरकारी सदस्यों में कोई सहमति नहीं बन पाई। दरअसल समिति का गठन ही इस प्रकार किया गया था कि उसका रुझान परियोजना के विस्तार के पक्षधरों की ओर ही रहता। इसमें न किसी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त और न स्थानीय पर्यावरणविद को शामिल करने की आवश्यकता महसूस की गई।

जबकि विकास लॉबी रपट आने से पहले ही जीत का प्रबंध कर चुकी थी। एक सुझाव आया कि मंदिर की आधारशिला को ऊंचा उठा लिया जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने के बावजूद यह मंदिर को बचाने की केवल एक औपचारिक रस्म होगी, उसे महज एक टापू में बदलने का प्रयास।

गंगा के अस्तिव को सबसे बड़ा खतरा तो उसके पानी की गुणवत्ता के नष्ट होने से पैदा होगा।

'गंगा तेरा पानी अमृत' – आज एक कपोल कल्पना बन गई है। वास्तविकता यह है कि कभी लंबे समय तक दूषित न होने वाला गंगा का पानी कालातंर में इंसानों के पीने के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। यही नहीं, यह उन जलचरों के अनुकूल भी नहीं रहेगा जिनके कारण किसी भी जलाशय या नदी को जीवित कहा जा सकता है।

गंगोत्री से ही गंगा में हर प्रकार की गंदगी डाली जाने लगती है। चाहे वह नगर पालिकाओं का गंदा पानी और मलमूत्र हो या औद्योगिक क्षेत्रों का विषाक्त द्रव और ठोस कचरा। इसी कारण पानी में वे धातुएं मिल जाती हैं, जो किसी भी जीव के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। कई नगरों में तो आज गंगा नहाने योग्य भी नहीं रही है। जब पानी में ऑक्सीजन सोखने की क्षमता घटने लगती है तो वह जीव जंतुओं को जीवनदायी ऑक्सीजन नहीं दे पाता और ऐसी अवस्था में नदियां अपने जैविक पदार्थों को पचाने में समर्थ नहीं रहतीं।

गंगा के बारे में कहा जाता है कि उसका पानी कभी खराब नहीं होता क्योंकि इसके पानी में किसी प्रकार का जैविक कचरा मिल जाने के बाद पानी कुछ मील की यात्रा में अपने आप शुद्ध हो जाता है लेकिन आज गंगा और शेष सभी नदियों में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि उसे पचाना गंगा की क्षमता के बाहर हो गया है। इसलिए वह आगे और आगे गंदी ही रहती है। दशकों पहले राजीव गांधी के शासनकाल में गंगा सफाई का अभियान आरम्भ किया गया था। इस मिशन के तहत देश और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अरबों रुपए खर्च हुए लेकिन गंगा साफ नहीं हुई।

कारण साफ है कि जिन स्रोतों से गंगा मैली होती है, वे ज्यों के त्यों रहे तो सफाई कहां से होती। फिर भी गंगा की सफाई गांधी परिवार का सपना रहा है, भले ही उस सपने को पूरा करने की सूझ–बूझ उनकी सरकारों में न रही हो। इसलिए जब ऐसी दो महिलाएं गंगा को बचाने के लिए सहमत हों, जो न केवल अलग–अलग स्वभाव और परिवेश से आती हैं अपितु जिनकी राजनीति की धारा भी एक–दूसरे के विपरीत है तो इसे महत्वपूर्ण घटना कह सकते हैं, बशर्ते यह केवल स्वांग भर न हो।

बहरहाल, उमा भारती गंगा अभियान की नेता की हैसियत से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलीं और उन्होंने महसूस किया कि सोनिया भी गंगा के मामले को पार्टी राजनीति से अलग रखेंगी। दरअसल गंगा और ऐसी अनेक नदियों को बचाने का यही एक रास्ता है क्योंकि हर पार्टी की सरकार नदियों को कथित विकास के तात्कालिक लाभ के लिए बलिदान करने का मन बना चुकी है।

जरूरी नहीं कि उत्तराखंड सरकार बड़ी पनबिजली योजनाओं के बारे में उमा भारती से सहमत हो। मनमोहन सरकार में भी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के पक्षधरों की कमी नहीं है। उमा कहती हैं कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाए और सोनिया गांधी ने माना कि इस पर विचार होना चाहिए। शायद सोनिया के मन में राजीव गांधी का सपना पूरा करने की आकांक्षा जगी हो। फिलहाल यह धारा के विरुद्ध चलने का काम है लेकिन धारा के विपरीत चलने से ही गंगा की धारा बचायी जा सकती है। ❑

हरिद्वार में संपन्न राष्ट्रीय विचार वर्ग

चीनी सामान खरीदकर न केवल हम राष्ट्रीय संपत्ति चीन की ओर धकेल रहे हैं, बल्कि शत्रु देश को अपने खिलाफ ताकत प्रदान कर रहे है। – प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

ज्ञान विज्ञान में विश्व गुरु रहा भारत आज एक छोटा–सा मोबाइल भी अपने यहां नहीं बना पा रहा। यह अत्यंत की चिंता एवं चिंतन का विषय है। – मुरलीधर राव

दिनांक 24–26 जून 2011 को नारायणी निवास कनखल, हरिद्वार में स्वदेशी जागरण मंच का उत्तर भारत का राष्ट्रीय विचार वर्ग संपन्न हुआ। 8 प्रांतों के 130 कार्यकर्ताओं के समक्ष उद्घाटन सत्र में श्री महेश शर्मा, पूर्व सांसद ने एकात्म मानववाद की वर्तमान परिपेक्ष्य में व्याख्या की। उनका कथन था कि आज विश्व की आर्थिक उथल–पुथल, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के वातावरण में एक बार फिर गांधी व दीनदयाल की पुस्तकों के कुछ पन्नें उलथने की जरूरत है। राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने वर्ग की महत्ता और आगामी कार्यक्रमों की व्याख्या की।

उन्होंने बताया कि गत चेन्नई की राष्ट्रीय बैठक में दो विषयों पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात तय हुई थी। एक विषय – 'भ्रष्टाचार व काला धन' के संदर्भ में पूरा भारत एकाग्रचित होकर जुटा है। परंतु दूसरा खतरा यानि 'खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश' के संकट के बादल पूरी तरह छाए हुए है। इसलिए दोनों विषयों को साथ–साथ चलाना पडेगा। साथ ही आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय की 150वीं जन्म वर्ष बनाने का कार्य भी स्फूर्ति देगा। वे "फॉर इन वन" थे। राष्ट्रवादी साहित्यकार, उत्प्रेरक उद्यमी, समाज सेवक व स्वदेशी वैज्ञानिक जैसे उनके चार आयाम थे।

श्री सुनील आंबेकर, राष्ट्रीय संगठनमंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ने एक सत्र में मुख्य वक्ता के नाते काले धन व भ्रष्टाचार की दलदल से उभरने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आवश्यकता पर बल दिया। विद्यार्थी परिषद अन्य राष्ट्रवादी ताकतों के साथ मिलकर पूरे देश में युवा शक्ति को इस कार्य में जुटायेगा। इस सत्र की अध्यक्षता करते हुए महामंडलेश्वर, स्वामी असंगानन्द, अध्यक्ष परमार्थ आश्रम ऋषिकेश व महामंडलेश्वर विज्ञानानन्द जी ने राजनीति में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों श्रेष्ट संतों ने आह्वान किया और आश्वासन दिया कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए संत समाज बढ़–चढ़कर हिस्सा लेगा। एक सत्र में प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा, राष्ट्रीय सह–संयोजक, स्व.जा.म., ने चीन के बढ़ते खतरे पर प्रकाश डाला। उनका कहना था कि चीनी सामान खरीदकर न केवल हम राष्ट्रीय संपत्ति चीन की ओर धकेल रहे हैं, बल्कि शत्रु देश को अपने खिलाफ ताकत प्रदान कर रहे है।

श्री मुरलीधर राव ने वर्तमान आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा करते हुए कहा कि ज्ञान विज्ञान में विश्व गुरु रहा भारत आज एक छोटा–सा मोबाइल भी अपने यहां नहीं बना पा रहा। यह अत्यंत की चिंता एवं चिंतन का विषय है। इस सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री बी.एन. खंडूरी, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड, ने कहा कि मैं केंद्रीय तथा प्रांतीय मंत्री का दायित्व निभाते हुए भी स्वदेशी के प्रतिपूर्ण आस्था रखता था और मेरा आज भी विश्वास है कि भारत स्वदेशी तकनीकी से ही उन्नति करेगा।

श्री शिव प्रकाश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय प्रचारक (रा.स्व.से.संघ), ने अत्यंत विदवत्तापूर्ण ढंग से जन आंदोलनों में संगठन की भूमिका विषय प्रतिपादित किया। उनका कहना था कि व्यक्तिवादी आंदोलनों की भ्रूण हत्या हो जाती है, और पूरे समाज को संगठित कर चलाए आंदोलन ही परिणामदायक और यशदायक होते है। श्री श्यामलाल यादव, इंडिया टूडे के वरिष्ठ पत्रकार, ने प्रोजेक्टर के माध्यम से सूचना के अधिकार विषय के विभिन्न आयामों को दर्शाया। इस सत्र की अध्यक्षता राज्य परिवहन मंत्री भी प्रकाश पंत ने की।

कार्यक्रम के समापन सत्र पर डॉ. चन्द्रमोहन ने सबका धन्यवाद किया। श्री अरूण ओझा, राष्ट्रीय संयोजक, स्व.जा.म., ने समारोप करते हुए प्राचीन भारत के गौरवशाली अतीत के कुछ पन्नों की व्याख्या की।

उनका कथन था कि ऐसा स्वर्णिम अतीत लिए भारत को पुनः विषय गुरू बनाने के लिए हम सबको कमर कसनी होगी। डब्ल्यू. टी.ओ. की वर्तमान दुरावस्था और नए परिप्रेक्ष्य में मुक्त व्यापार समझौतों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आर्शीवचन देते हुए स्वामी चिन्मानन्द, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ने देश में व्याप्त ग्रामीण व वनवासी क्षेत्र में बढ़ते असंतोश का उदाहरण सहित वर्णन किया और स्वदेशी आंदोलन को बलशाली बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. दुर्ग सिंह चौहान, कुलपति उत्तराखंड, तकनीकी विश्वविद्यालय ने की। हरिद्वार के सबसे छोटी आयु के बताए गए महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानन्द ने संतों, सैनिकों, लेखकों व आमजन को मिलजुलकर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न सत्रों में श्री अतुल कृष्ण महाराज, दिव्य सेवा प्रेम मिशन के संचालक श्री आशीष, श्री कुलदीप रतनू और अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए।

कार्यक्रम के अंत में महामंडलेश्वर रामेश्वरानंद जी ने सभी कार्यकर्ताओं को रूद्राक्ष माला व गंगाजल का प्रसाद दिया। गंगाजल ग्रहण करते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने गंगा बचाने का संकल्प को दोहराया। ❑